RAJHIN/2016/70516

Bhilwara/171/2026-2028

सच्चाई से रूबरू

smarthalchal.com

स्मार्ट हलचल

वर्ष-11 | अंक-01 | जयपुर, बुधवार, 01 जुलाई 2026 | मूल्य-4 रूपये

यमुना जल समझौते पर जयपुर में सीएम भजनलाल का भव्य रोड शो, स्वागत किया

यमुना जल समझौते के साथ राजस्थान में विकास के नए युग की शुरुआत: सीएम

जयपुर

यमुना जल समझौते के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास तक जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं, नारों और पारंपरिक स्वागत के साथ मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भाजपा कार्यकर्ताओं, विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र, ने मुख्यमंत्री को भगीरथी की उपमा देते हुए उनका पुष्प वर्षा कर, माला और साफा पहनाकर ऐतिहासिक एमओए के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यमुना जल समझौते के

लिए प्रदेश की आठ करोड़ जनता की ओर से बधाई देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। यमुना जल परियोजना के एमओए से 29 जून का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बन गया है। उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस एमओए के माध्यम से झुंझुनूं, चूरू और सीकर जिलों में यमुना का पानी आएगा, जिससे शेखावाटी की धरती सोना उगलेगी। पर्यटन और उद्योगों के बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शेखावाटी के साथ बड़ा अन्याय किया। यमुना जल का सिर्फ सपना दिखाया लेकिन कभी प्रयास नहीं किया गया। हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन यमुना जल परियोजना के लिए समन्वय और संवाद नहीं किया। आश्चर्य की बात यह है कि हरियाणा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यमुना जल समझौते को निरस्त करने का वादा किया था तब उस मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित थे। इसीलिए गहलोत ने इस योजना पर कोई कार्य नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में उन्होंने शेखावाटी क्षेत्र को यमुना का जल उपलब्ध कराने की जो बात की थी, उसे प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जा रहा है।

34 हजार करोड़ की परियोजना पर तेजी से काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने केंद्र और हरियाणा सरकार के सहयोग से यमुना जल परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए निरंतर कार्य किया है। 17 फरवरी 2024 को एमओयू कर तुरंत टास्क फोर्स का गठन किया और डीपीआर बनाई। आज लगभग 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की यह परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके अंतर्गत 3.6 मीटर की पाइपलाइन बिछाकर यमुना से शेखावाटी क्षेत्र के लिए पानी लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में राजस्थान का नाम पेपरलीक, भ्रष्टाचार, गैंगस्टर, महिला अत्याचार जैसी घटनाओं के साथ चर्चा में रहता था। आज परिस्थिति पूर्ण रूप से बदल गई है।

युवाओं को रोजगार, किसानों के कल्याण और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आज प्रदेश के किसानों को 26 जिलों में दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, हम दूसरे प्रदेशों को भी बिजली दे रहे हैं।

विकास कार्यों को मिल रही नई गति

भाजपा एक रोडमैप बनाकर प्रदेश का विकास सुनिश्चित कर रही है। पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लंबित योजनाओं को निरंतर गति प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में रामजल सेतु लिंक परियोजना, आईजीएनपी, गंग नहर, देवास, माही आदि परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की जनता ने जो भरोसा भाजपा सरकार के वादों पर किया है, उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा।

मुंबई में चलती स्कूल बस पर पेड़ गिरा, एक छात्र की मौत

11 बच्चे घायल, स्कूल से घर लौटते समय हादसा

मुंबई

मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर प्राइवेट स्कूल बस पर एक पेड़ गिर गया। बस में कुल 12 स्टूडेंट थे। उनमें से 11 का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बस में फंसे 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। स्कूल की छुट्टी के बाद प्राइवेट बस रोज की तरह बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी। तभी रोड नंबर 11 पर सड़क किनारे लगे पेड़ की बड़ी डालियां बस की छत पर आ गिरीं, जिससे बस का अगला और बीच का हिस्सा बुरी तरह दब गया। पेड़ गिरते ही बस के अंदर मौजूद बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग बस के पास पहुंचे। स्थानीय लोगों, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घायल बच्चों को बस से बाहर निकाला। मशीनों और कटर की मदद से पेड़ को काटा गया।

हादसे की खबर मिलते ही बच्चों के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। अपने बच्चों की चिंता में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और सभी की निगाहें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ट्रैफिक को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है।

ट्रेलर में घुसी प्राइवेट बस, चार की मौत

मथुरा

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस-वे पर आज तड़के करीब साढ़े तीन बजे हुए हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 19 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शवों की शिनाख्त कर ली है।

सूचना पाकर पहुंचे जिलाधिकारी (डीएम) चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। पुलिस अधीक्षक (देहात) सुरेश चन्द्र रावत ने बताया कि, गोला बस सर्विस की एक तेज

रफ्तार वोल्वो बस लखनऊ से 65 यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। मंगलवार सुबह करीब 3.41 बजे थाना राया क्षेत्र के राया कट के पास यमुना एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन 112-113 के बीच मैनपुरी के रहने वाले चालक उपदेश यादव को झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमों ने पहुंचकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बस में फंसे घायलों को निकालकर तुरंत एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल मथुरा भेजा, जहां कई लोगों की हालत गंभीर है। चार लोगों की मौत हो गई है।

खेत में बनी डिग्गी में डूबने से मां-बेटी की मौत

बीकानेर

बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के जालबसर गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में खेत की डिग्गी में डूबने से मां और उसकी मासूम बेटी की मौत हो गई। वहीं 12 वर्षीय बेटे को आसपास मौजूद लोगों ने समय रहते बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई।

जालबसर निवासी हनुमानराम जाट की पत्नी सावित्री (36) और बेटी ज्योति (6) की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। वहीं 12 वर्षीय बेटा विकास भी डिग्गी में चला गया था, लेकिन आसपास के लोगों ने तत्काल डिग्गी में छलांग लगाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

जनरल द्विवेदी आर्मी चीफ पद से रिटायर जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभाला

द्विवेदी बोले- सेना ने जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं, ऑपरेशन सिंदूर उदाहरण

नई दिल्ली

जनरल उपेंद्र द्विवेदी मंगलवार को आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

द्विवेदी ने कहा- दो सालों में भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारी, संतुलन और सतर्कता

मजबूत बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर इसका प्रमुख उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि आज मैं यह जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूं। वह एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं को कायम रखते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी।

द्विवेदी की जगह जनरल धीरज सेठ ने ली है। उन्होंने आज कार्यभार संभाल लिया है। सेठ भारत के 31वें आर्मी चीफ हैं। उन्हें भारतीय सेना में लगभग चार दशक का अनुभव है। उन्होंने दिसंबर 1986 सेना ज्वॉइन की थी।

जनरल द्विवेदी ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत हमारी तैनाती पूरी मजबूती और चौकसी के साथ रही। पश्चिमी मोर्चे पर भी सेना ने गंभीरता और संयम के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर मामले में भारतीय सेना ने स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाए हैं, जिससे न्यू नॉर्मल की नई परिभाषा स्थापित हुई है।

एसआईआर पर 23 विपक्षी दलों ने सीजेआई को लेटर लिखा

बोले- चुनाव आयोग की प्रकिया मनमानी और लोकतंत्र विरोधी

नई दिल्ली

चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को लेटर लिखा। डीएमके के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया मनमानी और लोकतंत्र विरोधी है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाना है, जबकि लोकतंत्र का आधार सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देना है।

लेटर पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) समेत 23 विपक्षी दलों और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हस्ताक्षर किए हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि 8 जून को इंडिया ब्लॉक की बैठक में लेटर भेजने का फैसला लिया गया था।

सरकार की ई20 योजना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जवाब

पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाना एक प्रयोग

सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का आदेश

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की सरकार की ई20 योजना पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक्सपेरिमेंट है। इसका पूरा असर अगले साल तक पता चलेगा। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने

कहा कि ई20 पॉलिसी में किसी बदलाव की योजना नहीं है। हालांकि, अलग-अलग कंपनियों को एथेनॉल का आवंटन मांग और उपलब्धता के आधार पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इसलिए मौजूदा सप्लाई पॉलिसी फिलहाल जारी रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिसमें एक कंपनी के एथेनॉल सप्लाई पर पुनर्विचार कर उसे बढ़ाने की मांग पर फैसला लेने को कहा गया था।

साथ ही कोर्ट ने इस मामले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर नोटिस जारी किया है।

यह मामला विन्प डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका से जुड़ा है। कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा था कि उसने सिर्फ एथेनॉल बनाने का प्लांट लगाया है। उसकी सालाना क्षमता करीब 9.90 करोड़ लीटर है, लेकिन 2025-26 के लिए उसे सिर्फ 3.92 करोड़ लीटर एथेनॉल सप्लाई का ऑर्डर मिला। जबकि उसने 9.26 करोड़ लीटर की बोली लगाई थी।

पत्नी और बेटे-बेटी का गला घोंटकर हत्या, फिर किया सुसाइड

खेत में मिले एक ही परिवार के चार शव

पाली। जोधपुर जिले के देचू थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ गांव में मंगलवार को एक ही परिवार के चार लोगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पाली जिले के रोहट क्षेत्र के बीठू गांव निवासी किसान गेनाराम, उसकी पत्नी और दो बच्चों के शव खेत में मिले। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गेनाराम ने पहले पत्नी और दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या की, इसके बाद खुद फंदे पर लटककर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने चारों शवों को हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है।

फलोदी जिला मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ गांव में मंगलवार सुबह पाली जिले के बीठू (रोहट) निवासी गेनाराम (35), उसकी पत्नी पुष्पा (32), बेटी खुशबू (13) और बेटे किशन (10) के शव मिले।

देचू थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि मौके पर महिला और दोनों बच्चों के शव जमीन पर पड़े मिले, जबकि गेनाराम का शव फंदे पर लटका हुआ था।

मोदी ने सचिवों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक

विभागीय दीवारें तोड़ें, योजनाओं का असर जमीन पर दिखना चाहिए

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सेवा तीर्थ में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं के लोगों के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग पर जोर दिया।

दो प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। पहला, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए विनियमन में सुधार और अन्य सुधार', जबकि दूसरा विषय 'आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना' था।

बैठक के दौरान विभिन्न

मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने इन दोनों विषयों के अनुरूप उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने के प्रयासों, विभिन्न क्षेत्रों की चुनौतियों और शासन एवं सेवा वितरण को बेहतर बनाने की भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की।

पीएम ने कहा- सभी विभागों को 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट' दृष्टिकोण अपनाते हुए विभागीय सीमाओं (साइलो) से बाहर निकलकर काम करना चाहिए। मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वित योजना से सरकारी कामकाज अधिक प्रभावी होगा।

पीएम ने गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग पर भी बल दिया और कहा कि यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा बेहतर और तथ्य आधारित निर्णय लेने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारी योजनाओं की सफलता का आकलन केवल उनके क्रियान्वयन से नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में आए वास्तविक बदलाव से किया जाना चाहिए।

सरकारी कार्यों, जन-केंद्रित मामलों में ढिलाई न हो: पीएम

पीएम ने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बैठक में उन्होंने सचिवों को गवर्नेंस और इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान केंद्रित रखने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि सरकारी कार्यों, खास तौर पर जन-केंद्रित पहलों में कोई ढिलाई या देरी न हो।

पीएम मोदी ने इससे पहले अगले 10 वर्षों के लिए सुधार प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की 'सुधार एक्सप्रेस' व्यवस्थागत बदलाव लेकर आई है और नागरिकों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ पहुंचाया है।

राजस्थान पुलिस में 100 इंस्पेक्टर के तबादले

एडीजी बीजू जॉर्ज जोसफ ने जारी किए ट्रांसफर आदेश

जयपुर

राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 100 पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) के तबादला आदेश जारी किए हैं। ये स्थानांतरण संबंधित अधिकारियों की स्वयं की प्रार्थना (Self Request) के आधार पर तत्काल प्रभाव से किए गए हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) बीजू जॉर्ज जोसफ की ओर से जारी आदेश के अनुसार निरीक्षकों को पुलिस आयुक्तालय जयपुर, जोधपुर, विभिन्न रेंज, सीआईडी-सीबी, एटीएस-एसओजी, एसीबी, जीआरपी, प्रशिक्षण संस्थानों और पुलिस मुख्यालय की अलग-अलग

शाखाओं में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

तबादला सूची में सबसे अधिक अधिकारियों की पोस्टिंग अजमेर रेंज, भरतपुर रेंज, जयपुर रेंज, जोधपुर रेंज, उदयपुर रेंज, कोटा रेंज, आयुक्तालय जयपुर, आयुक्तालय जोधपुर और सीआईडी-सीबी में की गई है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के प्रकरण या राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-16 (CCA Rule-16) के तहत कार्रवाई विचाराधीन या प्रस्तावित है, उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा, 19 जून को जारी आदेश के तहत सतपाल सिंह का अजमेर रेंज से जयपुर पुलिस आयुक्तालय किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है।

पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरित निरीक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जान जोखिम में डाल बुलडोजर से नाला पार, हेल्थ वर्कर ने बच्चों तक पहुंचाई पोलियो खुराक

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहुल स्पीति में स्वास्थ्य कार्यकर्ता पलजोम बुट्टी ने कर्तव्यनिष्ठा और साहस की अनूठी मिसाल पेश की है। बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक उफनते नाले को पार किया। यह घटना राष्ट्रीय सघन पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के दौरान तिगरट बूथ पर घटी, जहां पलजोम ने विषम परिस्थितियों में भी अपना दायित्व निभाया। पहाड़ों में बढ़ते तापमान के कारण लाहुल घाटी के नदी-नाले इन दिनों पूरे उफान पर हैं, और तिगरट का नाला भी इसी कारण पार करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। कोई सुरक्षित साधन न होने पर, पलजोम ने हिम्मत दिखाई और एक बुलडोजर की मदद से उफनते नाले को पार किया। इस असाधारण प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ, जिसने पूरे देश व प्रदेश में उनकी सराहना की लहर पैदा कर दी। कठिनतम परिस्थितियों में भी बच्चों तक समय पर पोलियो की खुराक पहुंचाने का उनका समर्पण प्रेरणादायक है। स्थानीय निवासियों, जिनमें नोरबू, दीपक, टशी और तेंजिन डोलमा शामिल हैं, ने उनके जज्बे को सलाम किया और उनके समर्पण को सराहा। लाहुल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने भी पलजोम बुट्टी को समाज के लिए एक प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद, पलजोम ने पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया है, जो हम सभी के लिए एक बड़ी सीख है।

पुलिस की सक्रियता से गुम हुआ बच्चा 48 घंटे के भीतर बरामद, परिजनों ने ली राहत की सांस

लोहरदगा (एजेंसी)। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के ननतिलो नावाटोली से पिछले 27 जुन को लापता हुए बच्चें को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सोमवार को कुडू व कैरो थाना क्षेत्र की सीमा से बरामद करते हुए परिजनों को सौंप दिया।बच्चें के बरामदगी होने से परिजनों ने राहत की सांस ली।बताया जाता है कि ननतिलो नावाटोली निवासी सालोनी उरांव ने कुडू पुलिस को आवेदन देकर बताया था कि मेरा 13 वर्षीय पुत्र राज अनुप उरांव 27 जुन की सुबह 10 बजें घर मे किसी को कुछ बताएं बगैर कही चला गया है।काफी खोजबीन के बाद भी बच्चे के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है।आवेदन मिलने के बाद थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बच्चे की खोजबीन शुरू किया।सोमवार को थाना प्रभारी अजीत कुमार को सूचना मिली कि इसी बच्चे की तरह दिखने वाला एक बच्चा तान पहाड़ी की तरफ देखा गया है।थाना प्रभारी ने खोजबीन के लिए दो अधिकारियों के साथ परिजनों को लेकर स्वयं निकल पड़े। सोमवार दोपहर लगभग दो बजे तान व हुदू गांव के बीच बच्चे को बरामद किया गया। बच्चें को लेकर पुलिस थाना पहुंची व कागजी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंप दिया।बच्चे की मां सालोनी उरांव ने बताया कि बच्चें के लापता होने के बाद दो दिनों से परिजन काफी परेशान थे।थाना प्रभारी अजीत कुमार की सक्रियता के बाद लापता बच्चे को 48 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद करते हुए परिजनों को सौंप दिया गया।

पोलियो खुराक के बाद दो बच्चियों की संदिग्ध मौत, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के विदिशा और झाबुआ जिलों में पल्स पोलियो अभियान के दौरान खुराक देने के बाद दो मासूम बच्चियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का दुखद मामला सामने आया है। दोनों ही घटनाएं रविवार की हैं, जहां परिजनों ने पोलियो ड्रॉप्स को ही बच्चियों की मौत की वजह बताया है। हालांकि, राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर बताया है कि पोलियो की दवा पूरी तरह सुरक्षित है और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पहली घटना विदिशा जिले की कुरवाई तहसील के ग्राम मैनखेड़ी की है, जहां अनिल अहिरवार की बेटी मानसी को सुबह पोलियो की खुराक दी गई थी, जिसके कुछ घंटों बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। विदिशा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. रामहित कुमार ने बताया कि उस बूथ पर मानसी के साथ उसकी बड़ी बहन सहित कुल 44 अन्य बच्चों को भी वही दवा पिलाई गई थी और सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। मौत की असली वजह जानने के लिए विसरा जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी घटना झाबुआ जिले के कल्याणपुरा ब्लॉक की है, जहां सुनील डामोर की 11 माह की बेटी पूजा ने भी पोलियो ड्रॉप्स लेने के कुछ समय बाद दम तोड़ दिया। झाबुआ के सीएमएचओ डॉ. एमएल चोपड़ा के अनुसार, जिस शीशी से पूजा को दवा दी गई थी, उसी से 19 अन्य बच्चों को भी खुराक दी गई थी, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य विभाग दोनों मामलों की गहराई से जांच कर रहा है।

उत्तराखंड : धामी सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा, डीबीटी के माध्यम से खातों में 93 करोड़

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के गरीब और श्रमिक परिवारों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने दलालों और बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सीधे मजदूरों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता राशि भेजनी शुरू की है। पिछले एक साल के भीतर श्रम कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य के 24,323 पंजीकृत श्रमिकों के खातों में कुल 93.06 करोड़ रुपये ट्रांसफर हो चुके हैं। हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा 4,400 से अधिक श्रमिकों को करीब 11 करोड़ रुपये की राशि बिना किसी विलंब के सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई। यह आर्थिक मदद असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों की रोजमर्रा और आपातकालीन जरूरतों को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इसमें बेटियों की शादी, परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता, महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप शामिल है, जिससे संकट के समय इन्हें ऊंचे ब्याज पर कर्ज न लेना पड़े। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि मजदूरों को पंजीकरण या लाभ के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, बल्कि प्रशासन खुद उनके पास पहुंचे। इसके लिए निर्माण स्थलों के पास वर्कप्लेस वेलफेयर कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां श्रमिकों का पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह मिल रहा है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आधुनिक तकनीक और सख्त डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया है, जिससे फर्जीवाड़ा पूरी तरह रुक गया है और सरकारी सहायता बिना किसी कटौती के सिर्फ वास्तविक हकदारों तक पहुंच रही है।

मनरेगा के नए मॉडल से राज्यों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ

–जयराम ने वीबी जी–रामजी योजना को संघीय ढांचे पर प्रहार बताया

नई दिल्ली (एजेंसी)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर प्रस्तावित विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी जी-रामजी योजना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि नई व्यवस्था से राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा और इससे देश के संघीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी बयान में कहा कि मनरेगा एक मांग-आधारित और अधिकार-आधारित रोजगार गारंटी योजना थी, जबकि नई व्यवस्था आवंटन-आधारित योजना के रूप में काम करेगी। उनके अनुसार प्रस्तावित मॉडल में कुल व्यय का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 40 प्रतिशत खर्च राज्यों को उठाना होगा। जयराम रमेश ने कहा कि जिस आवंटन फार्मूले को अपनाया जा रहा है, वहीं 16वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए इस्तेमाल किया गया था। उनका तर्क है कि यह फार्मूला राजस्व वितरण के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन व्यय वहन करने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि अनुदान व्यवस्था में कटौती और राज्यों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालने से पहले से ही कमजोर संघीय ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से व्यापक चर्चा किए बिना ही मनरेगा को समाप्त करने संबंधी विधेयक संसद से पारित कराया। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया। जयराम रमेश ने दावा किया कि कई राज्यों ने भी नई योजना को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। उनके अनुसार मध्यप्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे भाजपा शासित राज्यों ने भी अतिरिक्त वित्तीय भार को लेकर चिंता व्यक्त की है। वहीं कुछ राज्यों ने कृषि सीजन के दौरान प्रस्तावित 'ब्लैकआउट अवधि' का विरोध किया है, जिसमें योजना के तहत काम उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम पांच राज्यों ने ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि नई योजना के प्रभाव और उसके क्रियान्वयन को लेकर राज्यों की आशंकाओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

जयपुर महिला का पाकिस्तानी आतंकियों से कथित संपर्क : एटीएस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

जयपुर (एजेंसी)। जयपुर के वाटिका क्षेत्र से गिरफ्तार 36 वर्षीय बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा के मामले में राजस्थान एटीएस की जांच में कई गंभीर और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। महिला पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क रखने का आरोप है, जिसकी गहन पड़ताल हो रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार, महिला के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया खातों की प्रारंभिक जांच में पाकिस्तान सहित अन्य देशों से संचालित कई संदिग्ध प्रोफाइलों से संपर्क के संकेत मिले हैं। एटीएस का दावा है कि फेसबुक पर उसके अकाउंट की दोस्तों की सूची में बड़ी संख्या में विदेशी प्रोफाइल जुड़े हुए थे, जिसमें से कुछ की पहचान संदिग्ध खातों के तौर पर की जा रही है। जांच के दौरान कुछ इसतरह के नामों का खुलासा भी हुआ है, जिनका संबंध पूर्व में आतंकी गतिविधियों और प्रतिबंधित संगठनों से जोड़ा जाता रहा है। हालांकि, एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि इन संपर्कों की तकनीकी और फोरेंसिक जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। राजस्थान एटीएस के अनुसार, बबीता बीते दो वर्षों से कुछ विदेशी संपर्कों के संपर्क में थी। साइबर विशेषज्ञ उसके मोबाइल, सोशल मीडिया चैट और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की गहराई से जांच कर रहे हैं। कई डिलीट किए गए डेटा को पुन: प्राप्त करने के लिए फोरेंसिक साइंस लैब की मदद ली गई है, जो मामले की गंभीरता को दर्शाता है। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं को प्रभावित कर किसी संगठित 'लेडी स्लीपर सेल' नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा था। संदिग्ध संपर्कों और मोबाइल नंबरों का मिलान राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा डेटाबेस से कराया जा रहा है, साथ ही 100 से अधिक सोशल मीडिया प्रोफाइलों की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी डिजिटल साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच कराई जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मदद से इस मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे का पता लगाया जा सके।

दिल्ली में नई ईवी नीति 2026 घोषित: 1 जुलाई से लागू, प्रदूषण घटाने पर केंद्रित

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी महत्वाकांक्षी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी 2026 की घोषणा की है, जो 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होकर 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बताया कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ परिवहन वाली राजधानी बनाना है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पूरे देश में ईवी पर सबसे अधिक सब्सिडी और अन्य सुविधाएं देने वाला राज्य है।

यह नीति अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष सरकारी निवेश आकर्षित करेगी, जबकि नागरिकों को कर छूट और ईवी अवसंरचना के माध्यम से लगभग 15,000 करोड़ का समग्र लाभ मिलेगा। नीति के तहत, सभी प्योर ईवी वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। हालांकि, चार पहिया वाहनों के लिए यह छूट 30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों पर लागू होगी।

इस नीति में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया और ग्रामीण सेवा वाहनों सहित छोटे व्यावसायिक वाहनों को शामिल किया गया है। परिवहन आयुक्त निहारिका राय ने बताया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर पर विकसित किया जाएगा, जिसके पहले चरण में मुख्य मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। निजी तौर पर चार्जिंग सुविधा विकसित करने के लिए डिस्कॉम को भी प्रोत्साहित किया गया है। नीति के तहत, ईवी पर ली जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठाने के बाद वाहन को तीन साल तक किसी अन्य राज्य में पंजीकृत नहीं कराया जा सकेगा। दिल्ली सरकार के मंत्रियों, मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद ने इस नीति को प्रदूषण कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि देश के बड़े विशेषज्ञों से राय लेकर तैयार किया गया है ताकि हर मुद्दे पर गंभीरता से काम हो सके। यह नीति दिल्ली को देश में ईवी अपनाने में अग्रणी राज्यों में से एक बनाने के सरकार के प्रयासों को और गति देगी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सिब्बल की कविता से गरमाई सियासत

–'राम को लूटा, देश को लूटा' शीर्षक कविता से केंद्र सरकार पर साधा निशाना

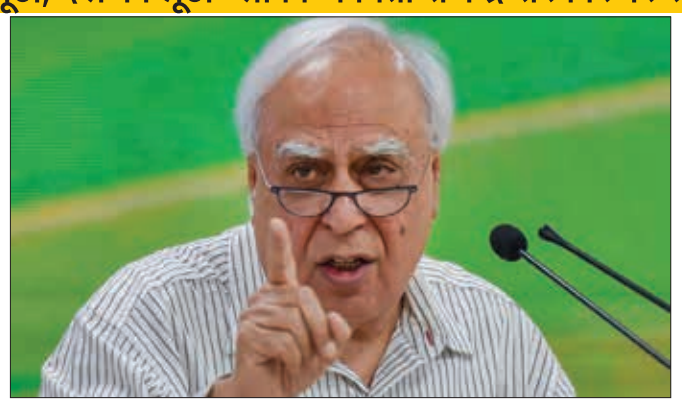

नई दिल्ली (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक कविता साझा करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनकी टिप्पणी के बाद इस मुद्दे ने नया राजनीतिक रंग ले लिया है।

कपिल सिब्बल ने अपनी पोस्ट में लिखा, ÷राम को लूटा, देश को लूटा, अच्छे दिन का नारा झूठा। ऐसे शासन को तोड़ देंगे, मिलकर देश को जोड़ देंगे। न दिलों का होगा बंटवारा, सबका देश है देश हमारा।÷ उन्होंने कविता की शुरुआत ÷इस सरकार को सत्ता से बाहर करें÷ जैसे शब्दों से करते हुए सरकार की नीतियों और शासन व्यवस्था पर सवाल उठाए। सिब्बल की यह काव्यात्मक प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा जारी है। अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने कथित भ्रष्टाचार, जवाबदेही और सामाजिक एकता जैसे मुद्दों को एक साथ जोड़ते हुए सरकार की आलोचना की। उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया कि देश में विभाजन की राजनीति के बजाय सामाजिक सद्भाव और एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिब्बल की यह टिप्पणी केवल एक साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ एक व्यापक राजनीतिक संदेश भी है। उनकी कविता में 'अच्छे दिन' के नारे और शासन की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल उठाए गए हैं। इधर, राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच भी जारी है। पुलिस इस प्रकरण में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसियों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है।

इस बीच, मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि मामले पर निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही विचार किया जाएगा।

आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी: बेंगलुरु कोर्ट ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को भेजा समन

–21 जुलाई, 2026 तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया

बेंगलुरु (एजेंसी)। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खड़गे और युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद नलपद को समन जारी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप पाटिल ने इस आपराधिक मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेकर माना कि दोनों नेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 356 के तहत मामला चलाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। कोर्ट ने मामले को आपराधिक केस के रूप में दर्ज करने का आदेश देकर दोनों आरोपियों को 21 जुलाई, 2026 तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। हालांकि, पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री दिनेश गुंडू राव के खिलाफ आगे की कार्रवाई बंद की है।

यह मामला बेंगलुरु निवासी आरएसएस कार्यकर्ता ए. तेजस द्वारा दायर की गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अक्टूबर 2025 में आरोपियों ने जानबूझकर आरएसएस और उसके सदस्यों को निशाना बनाकर सोशल मीडिया और मीडिया बयानों के जरिए संगठन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया था। शिकायत के अनुसार, खड़गे ने मंत्री पद पर रहते हुए पत्र लिखकर आरएसएस को सरकारी खेल के मैदानों और शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग करने से रोकने की मांग की थी, जिसे बाद में जानबूझकर मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। इसके अतिरिक्त, खड़गे द्वारा किए गए कुछ अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में संगठन के सदस्यों के खिलाफ अत्यधिक आपत्तिजनक और गरिमाहीन टिप्पणियां की गई थीं।

वहीं शिकायत में युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद के उस बयान का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं पर अमर्यादित और अश्लील टिप्पणी की थी।

शिकायतकर्ता ने दलील दी कि ये सभी बयान पूरी तरह से झूठे, दुर्भावनापूर्ण और संगठन तथा उसके समर्थकों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से दिए गए थे। आरोपियों द्वारा अपने बयानों पर माफी न मांगने और उनके ऑनलाइन मौजूद रहने से संगठन की प्रतिष्ठा को लगातार नुकसान पहुंच रहा है, जिसके बाद अदालत ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है।

बिजली संकट: प्लांट ठप, 10 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रही मान सरकार

लुधियाना (एजेंसी)। दशकों तक देश की हरित क्रांति में अग्रणी रहा पंजाब आज भीषण बिजली संकट से जूझ रहा है। गर्मियों के मौसम और धान की रोपाई के चरम पर पहुंचने के साथ ही राज्य की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सरकारी बिजली संयंत्रों की 6 इकाइयों के ठप होने से राज्य को नेशनल ग्रिड से 10 रुपये प्रति यूनिट तक की अत्यधिक महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस स्थिति ने किसान, उद्योग और आम जनता सभी को बेहाल कर दिया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है।

इस गंभीर संकट का मुख्य कारण सरकारी थर्मल प्लांटों की छह इकाइयों में आई तकनीकी खराबी है, जिससे राज्य में तत्काल 1,800 मेगावाट बिजली की कमी हुई है। लेहरा मोहब्बत स्थित गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट, जिसकी 920 मेगावाट क्षमता वाली चारों इकाइयां ठप पड़ी हैं, इस संकट का केंद्र बन गया है। यहां राख के अधिक जमाव और पुरानी तकनीकी कमियों को इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा, रोपड़ प्लांट की 30 साल से अधिक पुरानी इकाइयां भी अपनी तय उम्र पूरी कर चुकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समस्या वर्षों से रखरखाव और आधुनिकीकरण पर ध्यान न देने का परिणाम है, जिसने धीरे-धीरे राज्य को इस कगार पर ला खड़ा किया है।

मशीनी खराबी के साथ-साथ, मानवीय मोर्चे पर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। बिजली निगम के लगभग 1,852 आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल ने मरम्मत और बहाली के कार्यों को धीमा किया है, जिससे संकट और गहरा गया। कृषि प्रधान पंजाब के लिए समय अत्यंत नाजुक है, क्योंकि धान की रोपाई के लिए निरंतर बिजली आपूर्ति अनिवार्य है। कई जिलों में हो रही भारी कटौती से किसानों की फसल उत्पादन और आय पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। वहीं, उद्योग जगत भी महंगी और अनिश्चित बिजली आपूर्ति से परेशान है। बढ़ती उत्पादन लागत और पड़ोसी राज्यों के मुकाबले बिगड़ती औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के कारण पंजाब में नए निवेश आकर्षित करना मुश्किल हो गया है।

अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले एलजी सिन्हा ने की बाबा बर्फानी की पूजा

–3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा होगी शुरू

जम्मू (एजेंसी)। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सोमवार को बाबा बर्फानी की पूजा हुई। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पूजा में शामिल हुए। इस साल 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। यात्रा 28 अगस्त को खत्म होगी। कुल 57 दिनों तक यह यात्रा चलेगी। अधिकारियों के मुताबिक 15 अप्रैल से अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा रूट के लिए रवाना होगा।

प्रशासन ने बालटाल और चंदनवाड़ी में बेस अस्पताल शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा यात्रा के दोनों मार्गों पर भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन ने दोनों मार्गों पर बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी ज्यादातर तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि, चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक के मार्ग पर महागणेश टॉप के पास बर्फ हटाने का काम जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इसे अगले दो से तीन दिनों में काम पूरा कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के लिए दो रुट हैं, पहला 41 किलोमीटर लंबा पारंपरिक पहलगाम रुट और दूसरा 7 किलोमीटर लंबा बालटाल रुट। पहलगाम रुट अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक रुट है। यहां से पवित्र गुफा तक पहुंचने में आमतौर पर 3 से 4 दिन लगते हैं। इस मार्ग पर चढ़ाई धीरे-धीरे होती है, जिससे श्रद्धालुओं का शरीर ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के अनुकूल हो जाता है। साथ ही रास्ते में शेषनाग और पंचतरणी जैसे पौराणिक और धार्मिक महत्व वाले मंदिर के दर्शन भी होते हैं।

कैबिनेट फेरबदल की चर्चा के बीच पीएम मोदी की शीर्ष नौकरशाहों के साथ बैठक

नई दिल्ली (एजेंसी)। कैबिनेट फेरबदल की तेज होती अटकलों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को विभागीय सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस महामंथन का मुख्य उद्देश्य नियमों में ढील, उदारीकरण और सुधारों को गति देना है, ताकि व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके।

यह दो माह से भी कम समय में शीर्ष नौकरशाही के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी अहम बैठक होगी। पीएम मोदी सोमवार को सेशेल्स की आधिकारिक यात्रा समाप्त कर दिल्ली लौट रहे हैं, और मंगलवार को इस ब्रीफिंग में शामिल होने वाले है। इसके पहले 21 मई को उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए नियामक रोडमैप तैयार करने हेतु केंद्रीय मंत्रिपरिषद और केंद्रीय सचिवों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की थी।

बताया जा रहा है कि इस आगामी बैठक में उदारीकरण और सुधारों के अलावा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर खास ध्यान केंद्रित रहेगा। प्रत्येक सचिव को प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष अपनी प्रस्तुति के लिए तीन मिनट का समय दिया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि व्यापार और नागरिक जीवन को आसान बनाने के लिए उन्होंने उदारीकरण और सुधार एजेंडा लागू करने में क्या कदम उठाए हैं, आगे क्या कर सकते हैं और उनके क्या सुझाव हैं।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर विनियमन में ढील तथा सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस दिशा में दो अहम समितियां कार्यरत हैं। इसमें से एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट सचिव और नीति आयोग सदस्य राजीव गाबा कर रहे हैं, जिसका गठन 19 अगस्त 2025 को किया गया था। यह समिति गैर-वित्तीय क्षेत्र के नियमों, प्रमाणपत्रों, लाइसेंसों और अनुमतियों की समीक्षा कर एक आधुनिक और जनहितैषी नियामक ढांचा तैयार करने का काम कर रही है। दूसरी समिति, एक टास्क फोर्स है, जिसका नेतृत्व बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केके पाठक कर रहे हैं, जिसका गठन पिछले वर्ष हुआ था। कैबिनेट सचिवालय ने कुछ राज्यों में विनियमन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए चयनित सचिवों की भी नियुक्ति की है।

आईसीएआई भीलवाड़ा ब्रांच द्वारा सीए विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक इंटरैक्टिव सेशन आयोजित

एआई से नहीं घटेंगे अवसर, बल्कि और मजबूत होगा सीए प्रोफेशनः सीए सौरभ अजमेरा

इंटरैक्टिव सेशन में 100 से अधिक विद्यार्थियों और सदस्यों ने लिया भाग, परीक्षा तैयारी और करियर पर मिला मार्गदर्शन

स्मार्ट हलचल

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ब्रांच ऑफ आईसीएआई द्वारा सीए विद्यार्थियों के लिए एक विशेष इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चेयरमैन सीए सौरभ अजमेरा, तथा विशिष्ट अतिथि सेक्रेटरी, सीए निर्भीक गांधी, उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 100 से अधिक सीए विद्यार्थियों एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि सीए सौरभ अजमेरा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में एआई को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। उन्होंने कहा कि एआई चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अवसरों को कम नहीं करेगा, बल्कि यह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कार्य को अधिक प्रभावी, तेज़ और गुणवत्तापूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भविष्य में टैक्सेशन, ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, स्टार्टअप्स, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, वैल्यूएशन तथा अन्य कई क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध रहेंगे। इसलिए विद्यार्थियों को नई तकनीकों को अपनाने के साथ-साथ अपने ज्ञान एवं कौशल को निरंतर विकसित करना चाहिए। उन्होंने आगामी सीए परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन, आईसीएआई स्टडी मटेरियल पर विशेष ध्यान, बार-बार रिवीजन, मॉक टेस्ट एवं आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि अनुशासित एवं निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में सीए सौरभ अजमेरा ने अपनी जीवन यात्रा भी विद्यार्थियों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि प्रोफेशनल जीवन में चुनौतियाँ प्रत्येक व्यक्ति के सामने आती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प, सकारात्मक सोच और निरंतर परिश्रम के बल पर हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने संघर्ष, सीखने के अनुभव तथा नेतृत्व की यात्रा का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सीए निर्भीक गांधी ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी देश के सबसे प्रतिष्ठित एवं सम्मानित प्रोफेशन्स में से एक है। बदलते आर्थिक एवं तकनीकी परिवेश में योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रोफेशनल एथिक्स, सतत अध्ययन एवं नई तकनीकों को अपनाने पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने एआई परीक्षा की तैयारी, करियर विकल्प, प्रैक्टिस, इंडस्ट्री तथा प्रोफेशन से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे, जिनका दोनों अतिथियों ने विस्तारपूर्वक समाधान किया। यह इंटरैक्टिव सत्र विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। इस अवसर पर भीलवाड़ा ब्रांच के चेयरमैन सीए दिनेश सुथार ने कहा कि ये भीलवाड़ा के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि सौरभ अजमेरा भीलवाड़ा के भोजरास गाँव से मुंबई जाकर आईसीएआई के वेस्टर्न रीज़न जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा सीए और 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का प्रतिनिधत्व कर रहे है जो संख्या की दृष्टि से पूरे भारत के सदस्यों और विद्यार्थियों का लगभग एक तिहाई से ज्यादा है। शाखा का उद्देश्य विद्यार्थियों को श्रेष्ठ मार्गदर्शन उपलब्ध कराना तथा उन्हें राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से जोड़ना है, जिससे वे बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी विद्यार्थियों के हित में ऐसे शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास से जुड़े कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे। अंत में ब्रांच के सचिव सीए पुलकित राठी ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों व उपस्थित विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सीए सत्यनारायण लाठी, सीए आलोक सोमानी, सीए नवीन वगेरीचा, सीए मनीष जिंदल, सीए सुनील सोमानी, सीए मुरली अटल, सीए अक्षय सोडानी एवं सीए अवधेश शर्मा सहित शाखा के वरिष्ठ सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में 100 से अधिक सीए विद्यार्थियों एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक बताते हुए इसकी सराहना की तथा भविष्य में भी ऐसे मार्गदर्शन एवं व्यक्तित्व विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा व्यक्त की।

शिवम् अजमेरा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त

राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक संपन्न, संगठन के विस्तार, सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार को लेकर की विस्तृत चर्चा

स्मार्ट हलचल

भीलवाड़ा। राष्ट्रीय बजरंग दल भीलवाड़ा की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक सांवरिया सेठ मंदिर, नौगांवा परिसर में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, आगामी कार्य योजनाओं और सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक घोषणा भी की गई। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष रितेश गुर्जर ने बताया कि सनातन धर्म के प्रति गहरी लग्न, निष्ठा एवं ईमानदारी से किए गए कार्यों को देखते हुए शिवम् अजमेरा को राष्ट्रीय बजरंग दल के भीलवाड़ा जिले के व्यापार प्रकोष्ठ का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिलाध्यक्ष रितेश गुर्जर ने नियुक्ति पत्र सौंपते हुए आशा व्यक्त की कि नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष शिवम् अजमेरा के नेतृत्व में व्यापार जगत में संगठन बेहद मजबूत होगा। वे अपने बेहतरीन प्रयासों से भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रीय बजरंग दल को एक नई ऊँचाई पर लेकर जाएँगे। इस अवसर पर बनवारी गाडरी, देवीलाल सुथार, दीपक तुर्किया, ऋषभ जैन, विमेश रांका, रामपाल, सुशील श्रीश्रीमाल, श्रेयांश जैन, गिरीराज शर्मा, राहुल अग्रवाल, ऋषभ श्रीश्रीमाल, मनीष बड़ौला, शिव धुप्पड़, अभिषेक आंचलिया, निखिल बापना, नीरज आंचलिया, भावेश बाबेल, कपिल गुप्ता, कुशकांत शर्मा, कन्हैयालाल सोनी सहित उपस्थित थे।

अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग

स्मार्ट हलचल

लाडपुरा। 30 जून 2026 भारतीय किसान संघ, चित्तौड़ प्रांत (भीलवाड़ा) ने अफीम उत्पादक किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

जिला आपदा प्रमुख पुष्करलाल मीणा (ग्राम बराऊनी, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा) ने बताया कि सीपीएस पद्धति लागू होने से किसानों एवं अफीम मजदूरों का पारंपरिक रोजगार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि डोडा-चूरा नष्टीकरण की स्पष्ट नीति नहीं होने से निर्दोष किसानों को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार डोडा-चूरा के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/29 के दुरुपयोग पर रोक लगाए।

संघ ने सरकार से डोडा-चूरा उचित मूल्य पर खरीदने अथवा नष्टीकरण की स्थिति में किसानों को उचित मुआवजा देने तथा किसानों से स्वघोषणा पत्र लेकर खेतों में ही डोडा-चूरा को खाद के रूप में नष्ट करने की अनुमति देने की मांग की।

ज्ञापन के दौरान जिला अध्यक्ष भेरूलाल आचार्य, प्रदेश अफीम आयाम प्रमुख बद्रीलाल जाट, जिला अफीम आयाम प्रमुख रामपाल जाट, जिला मंत्री लादूलाल जाट, जिला आपदा प्रमुख पुष्करलाल मीणा सहित भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी एवं किसान उपस्थत रहे।

नारायणपुरा की चरागाह व बिलानाम भूमि पर मेवदा के ग्रामीणों का कब्जा, भूमि दी ठेके पर

स्मार्ट हलचल

शाहपुरा। पंचायत समिति की अरनिया घोड़ा ग्राम पंचायत के नारायणपुरा पटवार हलका क्षेत्र की लगभग 25 बीघा चरागाह व बिलानाम भूमि पर निकटवर्ती मेवदा के ग्रामीणों ने कब्जा कर उस भूमि पर अवैध रूप् से तालाब का निर्माण कर इसे ठेके पर दे दिया है। राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी में भी इसकी रिपोर्ट नहीं करने पर मंगलवार को नारायणपुरा के आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसीलदार कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया तथा पांच घंटे का इंतजार करने के बाद देर सांय तहसीलदार के आने पर उनको ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने नारायणपुरा की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

पूर्व पार्षद भगवान सिंह यादव, महेंद्र कुमावत, गजराज कुमावत, गणेश गाडरी, गोपाल, भागचंद कुमावत, शिवराज, भेरूलाल भील, नारायण कुमावत, नाना गाडरी, भेरू नाथ, खाना गाडरी की अगुवाई में शाहपुरा पहुंचे नारायणपुरा के ग्रामीणों ने तहसीलदार भवंराज परिहार को दिये ज्ञापन में कहा है कि नारायणपुरा की चरागाह भूमि खसरा संख्या 411, 412, 413, 414, 415, 416, 420, 421, 422, 423 तथा बिलानाम खसरा संख्या 424, 425, 426, 427, 428, 429, में निकटवर्ती मेवदा के कतिपय प्रभावशाली लोगों ने पहले अतिक्रमण कर उस भूमि पर अवैध तरीके से तालाब का निर्माण कराकर उसे किसी बाहरी को ठेके पर दे दिया है।

इससे नारायणपुरा के ग्रामीणों के पशु चरने से वंचित हो रहे है। तथा ग्रामीणों को अपने पशु चराने के लिए मारे मारे फिरने को मजबूर होना पड़ रहा है। तहसीलदार को ज्ञापन देकर अतिक्रमण को हटाने, चरागाह व बिलानाम भूमि का सीमा ज्ञान करा कर नारायणपुरा के ग्रामीणों को पशुओं को चराने के लिए सौंपने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसा न होने पर ग्रामीण आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

तहसीलदार परिहार ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच करा कर कार्रवाई के निर्देश गिरदावर को दिये है।

राजस्थान में शिक्षा की अलख जगा रहा हिन्दुस्तान जिंक, छह इकाइयों को मिला शिक्षा विभूषण प्रतिष्ठित सम्मान

2017 से अब तक शिक्षा पर 551 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

स्मार्ट हलचल

भीलवाड़ा। विश्व की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक और शीर्ष चांदी उत्पादक कंपनी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को 30वें भामाशाह सम्मान समारोह में 6 इकाईयों को सम्मानित किया गया। भामाशाह पुरस्कार हिन्दुस्तान जिंक के रामपुरा आगुचा माइन, चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर, जावर माइन्स, राजपुरा दरीबा कॉम्प्लेक्स, जिंक स्मेल्टर देबारी एवं कायड माइन को को शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक योगदान के लिए शिक्षा विभूषण प्रदान किया गया। यह लगातार 11वां वर्ष है जब राजस्थान सरकार ने परिवर्तनकारी शैक्षिक पहलों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हिंदुस्तान जिंक को सम्मानित किया है। कंपनी ने 2017 से विभिन्न शिक्षा हस्तक्षेपों में 551 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जिससे सालाना 2 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यह पुरस्कार बिडला आडिटोरियम सभागार में आयोजित पुरस्कार समारोह में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, अतिरिक्त शिक्षा सचिव राजेश यादव ने राज्यभर से चयनित 145 भामाशाहों एवं 99 प्रेरकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राजस्थान के मिड डे मिल आयुक्त विश्व मोहन शर्मा, समसा की राज्य परियोजना निदेशक डॉ रश्मि शर्मा, शिक्षा निदेशक सीता राम जाट, संयुक्त निदेशक महेन्द्र खींची भी मौजूद थे। जिसे हिन्दुस्तान जिंक की इकाइयों रामपुरा आगुचा माइन के आइबीयू सीईओ राममुरारी, चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर के पर्यावरण प्रमुख मनीषा भाटी, हेड एचआर ममता शर्मा, देबारी जिंक स्मेल्टर के एसबीयू निदेशक विवेक यादव, हेड सीएसआर रूचिका चावला, दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स के हेड सीएसआर अभय गौतम, जावर माइंस के वित्त प्रमुख अमित मालानी, कायड माइंस के हेड राजेश चौधरी एवं सीएसआर टीम ने प्राप्त किया। विगत 9 वर्षो में, हिन्दुस्तान ज़िंक ने शिक्षा के क्षेत्र में सीएसआर के तहत् सामाजिक विकास में 551 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर 83 करोड़ रुपये जिनमें कक्षा कक्षों का निर्माण, शौचालय, खेल के मैदान, पीने के पानी की सुविधाएं और विद्युतीकरण और दीर्घकालिक शिक्षा प्रयासों हेतु 468 करोड़ रुपये शामिल हैं। इनमें नंद घर जो कि आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बचपन की देखभाल शामिल है, शिक्षा संबल, ग्रामीण छात्रों वशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा जीवन तरंग,उच्च शिक्षा हेतु ऊंची उड़ान, ग्रामीण बलिकाओं के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और कंपनी-संचालित स्कूलों के लिए सहयोग शामिल हैं। हिन्दुस्तान जिंक के शिक्षा कार्यक्रम से प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक बच्चें लाभान्वित हो रहे हैं, जिसका स्कूल नामांकन, विशेष रूप से किशोर बालिकओं के विद्यालय से जुड़ाव, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सीखने के परिणामों पर उल्लेखनीय प्रभाव हुआ है। राज्य में कक्षा 10वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत 2007 में 47 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 92.53 प्रतिशत हो गया है, जिसमें बालिकाएं लगातार बालकों का से बेहतर प्रदर्शन रहा हैं। जहां पिछले 10 वर्षो में राजस्थान का औसत परिणाम लगभग 67.66 प्रतिशत रहा, वहीं शिक्षा संबल से जुड़े 37 स्कूलों ने 100 प्रतिशत परिणाम हासिल किया है। हिंदुस्तान जिंक का शिक्षा संबल कार्यक्रम ग्रामीण राजस्थान में वंचित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए और अधिक प्रयास करते हुए, कंपनी ने राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अगले पांच वर्षो में प्रदेश में शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 36 करोड़ रुपये का निवेश होगा। हिंदुस्तान जिंक के प्रयासों में शिक्षा के साथ ही ग्रामीण महिलाओं और किसानों का उत्थान, स्वास्थ्य सेवा, जल संरक्षण को बढ़ावा देकर, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे में सुधार और स्थायी आजीविका के लिए भी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। इन पहलों ने सामूहिक रूप से 4 हजार से अधिक गांवों में 26 लाख से अधिक लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

उम्मेद सागर गोलीकांड, कोर्ट ने तीन आरोपियों को भेजा 2 दिन के रिमांड पर

सरकारी डाकबंगले में शराब पार्टी पर उठे सवालय पुलिस प्रतिष्ठित युवकों की भूमिका भी खंगाल रही

स्मार्ट हलचल

शाहपुरा। उम्मेद सागर बांध स्थित जल संसाधन विभाग के डाकबंगले में रविवार को दोस्तों की पार्टी के दौरान हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए कई पहलुओं पर जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, रविवार दोपहर आधा दर्जन युवक उम्मेद सागर बांध क्षेत्र में पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान आपसी कहासुनी विवाद में बदल गई और अचानक बंदूक से फायर हो गया। फायरिंग में गाडरी खेड़ा निवासी महेंद्र कहार गंभीर घायल हो गया। गोली के छर्रे उसके पैर में लगे, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। उसे तत्काल शाहपुरा जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया।

शाहपुरा थाना पुलिस ने पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश विष्नोई के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद नायक (सेवनी), सूरज हरिजन (उदयभान गेट) और किशन बागरिया (गांछा बस्ती) शामिल हैं। तीनों को शाहपुरा एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां पूछताछ और बरामदगी के लिए दो दिन के रिमांड पर सौंपा गया।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि विनोद नायक ने टोपीदार बंदूक से फायर किया था। घायल महेंद्र के पैर में तीन छर्रे लगे हैं और उसका उपचार भीलवाड़ा में जारी है। घटना के समय उसके साथ किशन गुर्जर और टिल्लू गुर्जर भी मौजूद थे।

जांच में एक बड़ा सवाल यह भी उभरकर सामने आया है कि सरकारी डाकबंगले में पार्टी कैसे हुई। सूत्रों के अनुसार पार्टी में शाहपुरा के कुछ प्रतिष्ठित परिवारों से जुड़े युवक भी मौजूद थे। पुलिस अब उनकी भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।

साथ ही डाकबंगले में तैनात कार्मिक की भूमिका भी जांच के घेरे में है। पुलिस यह पता लगा रही है कि कर्मचारी मौके पर मौजूद था या नहीं, और क्या उसे पार्टी की जानकारी थी।

पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं। हथियार की बरामदगी, पार्टी आयोजकों और मौके पर मौजूद अन्य युवकों की भूमिका से पर्दा उठना अभी बाकी है।

ब्यावर-विजयनगर के 20 बड़े भवन मालिकों को 1 करोड़ की उपकर वसूली के आदेश

30 दिन में टैक्स जमा नहीं किया तो लगेगा 100% जुर्माना, जिला कलेक्टर करेंगे संपत्ति कुर्क; नामी स्कूल, होटल, रिसॉर्ट और डेवलपर्स निशाने पर

स्मार्ट हलचल

ब्यावर। श्रम विभाग ब्यावर ने भवन निर्माण मालिकों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के रियल एस्टेट और व्यावसायिक जगत में हड़कंप मचा दिया है। विभाग ने 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996' के तहत तय समय पर टैक्स (ष्टद्गह्यह्) जमा नहीं कराने वाले 20 बड़े भवन व संस्थान मालिकों के खिलाफ एकतरफा उपकर निर्धारण आदेश जारी किए हैं। इन सभी डिफाल्टरों को लगभग एक करोड़ रुपये की बकाया राशि 30 दिनों के भीतर सरकारी खाते में जमा कराने का कड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि 30 दिन की समय-सीमा के भीतर यह राशि जमा नहीं की गई, तो दोषियों पर 100 प्रतिशत पेनल्टी (जुर्माना) ठोक दी जाएगी। इसके बाद भी लापरवाही बरतने पर मामलों को 'राजस्व वसूली अधिनियम' के तहत जिला कलेक्टर के समक्ष भेजकर संपत्ति कुर्की की अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नक्शा पास होने के बाद भी अंतिम असेसमेंट जरूरी

विभाग ने साफ किया है कि कोई भी निर्माणकर्ता, चाहे उसने नगर परिषद या विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवाते समय अनुमानित उपकर जमा ही क्यों न करवा दिया हो, उसे निर्माण पूरा होने के बाद श्रम विभाग कार्यालय आकर अंतिम उपकर निर्धारण राशि जमा कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

इन 20 डिफाल्टरों और संस्थानों की खुली पोल

धर्मेन्द्र तिवाड़ी पुत्र प्रकाश तिवाड़ी, विजयनगर, रामदेव टेलर पुत्र रामपाल, विजयनगर,'स्वर्णगंगा इ फ्र ा ड े व ल प स ् ' ' (गणपतलाल),'आर. टेक कैपिटल होम्स','एकलव्य एकेडमी' (कमला चौहान पत्नी गोविन्द चौहान),'स्वर्णगंगा डेवलपर्स' (केशव कुमार पुत्र गणपतलाल),'आर. टेक कैपिटल हाईस्ट्रीट','लिटिल चैम्प स्कूल','रानीबाग रिसोर्ट', 'जीवन श्री रेस्टोरेंट एण्ड होटल' (कमला चौहान पत्नी जीवन),'जीवन श्री स्टील एण्ड ग्लास' (कमला चौहान), 'घूमर होटल' (विरेन्द्र गुर्जर पुत्र पंछी गुर्जर),'रीगल कॉम्प्लेक्स' (घनश्याम दास पुत्र बंसीलाल),रामपाल सांखला पुत्र माधोलाल, 'चौधरी मार्केट', ,'हितेश चिल्ड वाटर' (बुद्धाराम भाटी),'न्यू पूनम होटल' (लक्ष्मण सिंह पुत्र किशनाराम),'होटल अरमान वेज एण्ड नॉनवेज', ब्यावर,ज्योति जैन पत्नी कमल कुमार जैन, ब्यावर,पी.पी.एस. मैरिज गार्डन, ब्यावर

क्या कहता है कानून? क्यों वसूला जाता है यह टैक्स?

1% निर्माण टैक्स का नियमः राजस्थान में 27 जुलाई 2009 के बाद बने सभी सरकारी, कॉमर्शियल (व्यावसायिक) और आवासीय भवनों पर निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर लागू है। इस राशि का इस्तेमाल गरीब मजदूरों की कल्याणकारी योजनाओं (जैसे बेटी की शादी, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता) के लिए किया जाता है।

किसे छूट, किस पर शिकंजा?ः जिन आवासीय घरों की कुल निर्माण लागत 10 लाख रुपये से कम है, उन्हें इस टैक्स से पूरी छूट है। लेकिन 10 लाख से अधिक की लागत वाले घरों और सभी व्यावसायिक भवनों (दुकान, मॉल, होटल, स्कूल) पर 1% उपकर देना ही होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर 24% ब्याजः निर्माण शुरू करने के 30 दिनों के भीतर श्रम विभाग को सूचना देना और 60 दिनों के भीतर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भारी जुर्माना वसूला जाता है।

धाकड़ महासभा भारतवर्ष में बालूराम धाकड़ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत

स्मार्ट हलचल

शाहपुरा (भीलवाड़ा)। शाहपुरा-श्री धाकड़ महासभा भारतवर्ष में शाहपुरा के बालूराम धाकड़ को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किए जाने पर समाज में खुशी की लहर है। उनकी नियुक्ति पर समाजजनों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।

श्री धाकड़ महासभा भारतवर्ष के राष्ट्रीय संरक्षक इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ (पूर्व जिला प्रमुख, भीलवाड़ा) तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र नागर (पूर्व संसदीय मंत्री एवं विधायक, खानपुर) के नेतृत्व में यह मनोनयन किया गया।

श्री धाकड़ महासभा भारतवर्ष के शाहपुरा तहसील अध्यक्ष सत्यनारायण धाकड़ ने बताया कि बालूराम धाकड़ लंबे समय से समाज हित के कार्यों में सक्रिय रहे हैं। उनके अनुभव, सकारात्मक सोच और संगठनात्मक क्षमता का लाभ समाज को मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बालूराम धाकड़ समाज के नवाचार, सुदृढ़ीकरण और सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे।

नियुक्ति के बाद समाज के विभिन्न पदाधिकारियों एवं समाजजनों ने बालूराम धाकड़ का अभिनंदन करते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

तिरंगे की आन पर प्राण न्योछावर करने वाले अमर शहीद बीरबल सिंह जीनगर का बलिदान दिवस मनाया, समाज ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

स्मार्ट हलचल | चित्तौड़गढ़

अखिल भारतीय जीनगर समाज चित्तौड़गढ़ द्वारा समाज के आराध्य, राष्ट्रभक्ति के अद्वितीय प्रतीक और देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर शहीद बीरबल सिंह जीनगर (ढालिया) का बलिदान दिवस अगाध श्रद्धा, गौरव और सम्मान के साथ मनाया गया। समाज के जिला अध्यक्ष श्री राजेश जीनगर के नेतृत्व में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में भारी संख्या में समाजजनों ने शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकों और युवाओं ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उनके अद्वितीय साहस, राष्ट्रप्रेम और ऐतिहासिक बलिदान को अत्यंत आदरपूर्वक नमन किया।

गोलियां खाने के बाद भी बुलंद रखे थे देश भक्ति के नारे:

कार्यक्रम के दौरान शहीद के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए समाज के सचिव नवरतन जीनगर ने बताया कि अमर शहीद बीरबल सिंह जीनगर (ढालिया) राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के मूल निवासी एवं भारत मां के सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े हुए थे और उन्होंने अंग्रेजी शासन तथा तत्कालीन रियासती दमन के विरुद्ध हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर संघर्ष किया। आज ही के दिन यानी 30 जून 1946 को रायसिंहनगर में आयोजित प्रजा परिषद के सम्मेलन के दौरान जब दमनकारी पुलिस ने क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज और अंधाधुंध गोलीबारी की, तब बीरबल सिंह तिरंगा लेकर सबसे आगे चल रहे थे। उनकी जांघ में अंग्रेजों की तीन गोलियां लगीं, वे लहूलुहान होकर गिर पड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया और अंतिम सांस तक 'भारत माता की जय' तथा 'इंकलाब जिंदाबाद' के गगनभेदी नारे लगाते रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद 1 जुलाई 1946 को उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण विसर्जित कर दिए।

समारोह में यह प्रबुद्ध समाजजन रहे उपस्थित:

जीनगर समाज चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष राजेश जीनगर की अध्यक्षता में आयोजित इस गौरवमयी कार्यक्रम में सचिव नवरतन जीनगर, एसबीआई के पूर्व शाखा प्रबंधक प्रहलाद राय चौहान, सांवरिया जिला अस्पताल के पूर्व नर्सिंग अधीक्षक छगनलाल टांक, भारतीय दूरसंचार विभाग के तेजमल सिसोदिया, कोषाध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानाचार्य अंबालाल चितारा, खूबचंद पड़िहार, ओम प्रकाश वर्मा (गुड्डू भाई), समाज कल्याण अधिकारी चंद्र प्रकाश जीनगर, रीको अधिकारी संदीप सोनगरा, रूहरूप्राचार्य राकेश पड़िहार, सीताराम सिसोदिया, मगनलाल सिसोदिया, सुरेश चौहान, भागचंद पंवार, हितेश पंवार, सांवरिया जिला अस्पताल के फार्मासिस्ट उमेश चौहान, जिला आयुर्वेद अस्पताल के कम्पाउंडर अनिल सिसोदिया, राकेश पड़िहार, कैलाश पंवार घोसुंडा, अनिल पड़िहार, रजत जीनगर, राहुल टांक, भरत जीनगर, मोनू पड़िहार, विजय पड़िहार, गीता जीनगर तथा गोविंद जीनगर सहित बड़ी संख्या में समाज की मातृशक्ति, युवा और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

युवाओं को दी शहीद के आदर्शों को अपनाने की सीख, दो मिनट का रखा मौन:

कार्यक्रम में मौजूद समाज के वरिष्ठ जनों ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि शहीद बीरबल सिंह जीनगर का जीवन हमें राष्ट्रप्रेम, सर्वोच्च त्याग, साहस और तिरंगे के सम्मान के लिए सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। समाज के प्रत्येक युवा को उनके जीवन और आदर्शों से सीख लेकर राष्ट्र एवं समाज की निःस्वार्थ सेवा के लिए आगे आना चाहिए। इसके बाद सभी समाजजनों ने शहीद की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर उन्हें अपनी भावभीनी और सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके विजन को जन-जन तक पहुँचाने का अटूट संकल्प लिया।

महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन

स्मार्ट हलचल | निंबाहेड़ा

राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) निंबाहेड़ा इकाई द्वारा सोमवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निंबाहेड़ा में स्नातक स्तर की विभिन्न कक्षाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर महाविद्यालय प्राचार्य के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्तमान समय में महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या सीमित होने के कारण अनेक छात्र-छात्राओं को प्रवेश से वंचित होना पड़ सकता है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की स्नातक कक्षाओं के लिए कुल 403 सीटें स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में तीनों संकायों में लगभग 600 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ऐसे में आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए सीटों में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि निंबाहेड़ा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए इसी महाविद्यालय पर निर्भर हैं। यदि सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो अनेक योग्य एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संगठन ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की सीटों में शीघ्र वृद्धि करने की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष दीपक धाकड़, ब्लॉक अध्यक्ष भंवरसिंह शक्तावात , जिला सचिव नवरत्न प्रजापत, हर्षित सेन, आदित्य पहाड़िया, समकित जैन, भूपेन्द्र टांक ,राजू मेघवाल दुर्गेश कुमावत, तनीष माली, तनीश पाटीदार, नन्दकिशोर गायरी, शिवम, पुष्कर कुमावत, आदित्य जाट, कृष्णा मीणा, करण सिंह, नीलम राणावत, योगिता, लक्की, भावना आदि मौजूद थे।

संतोष ट्रॉफी प्लेयर मनदीप सिंह सोलंकी एवं शुभम सिंह सहित राजस्थान टीम का हुआ सम्मान

स्मार्ट हलचल | बीकानेर/चित्तौड़गढ़

संतोष ट्रॉफी में राजस्थान फुटबॉल टीम के शानदार प्रदर्शन करने पर राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा पूरी चित्तौड़गढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ी मनदीप सिंह सोलंकी एवं शुभम सिंह सहित पूरी टीम का सम्मान किया गया और नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। चित्तौड़गढ़ के दोनों खिलाड़ियों के सम्मानित होने पर जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष पूरण आंजना ने दोनों को बधाई शुभकामनाएं दी। साथ ही सम्मान समारोह में उपस्थित जिला फुटबॉल संघ सेक्रेटरी फैसल खान, जॉइंट सेक्रेटरी धर्मेंद्र सिंह तंवर,कार्यालय प्रभारी जाकिर हुसैन संतोष ट्रॉफी प्लेयर एवं डी लायसेंस कोच शाहिद हुसैन और अजय प्रजापत मोहम्मद, मोहम्मद अकरम ने भी दोनों खिलाड़ियों को बधाई शुभकामनाएं दी।

बीकानेर के पशु विज्ञान विश्विद्यालय में स्थित ऑटोडेरियम में सोमवार को राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान टीम को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल, सेक्रेटरी दिलीप सिंह शेखावत, पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय बाली, महिला विंग चेयरपर्सन रोशनी टांक, कोषाध्यक्ष कैलाश चंद्र खटीक सहित मंचासीन अतिथियों ने जिला फुटबॉल संघ चित्तौड़गढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ी मनदीप सिंह सोलंकी एवं शुभम सिंह को फुटबॉल कैप एवं उपरणा ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंटकर नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ज्ञातव्य है के गत संतोष ट्रॉफी में राजस्थान फुटबॉल टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत सेकंड राउंड में क्वालीफाई किया था जिससे पूरे राजस्थान के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सभी ने किसी न किसी माध्यम से टीम को बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की। चित्तौड़गढ़ जिले से मनदीप सिंह और शुभम सिंह ने भी राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व कर जिले का मान बढ़ाया था। बेहतर प्रदर्शन के फलस्वरुप पूरी राजस्थान टीम को सम्मान के साथ राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी दिलीप सिंह शेखावत द्वारा पूरी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए एक लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की गई।

बीकानेर में राजस्थान फुटबॉल संघ की वार्षिक साधारण सभा आयोजित

प्रदेश के फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प

स्मार्ट हलचल | निंबाहेड़ा/बीकानेर

बीकानेर में राजस्थान फुटबॉल संघ की 'वार्षिक आम बैठक' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश भर के फुटबॉल संघ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और राजस्थान में खेल के विकास को लेकर भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई।

बैठक की अध्यक्षता राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल ने की। उनके साथ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से पंजाब से आए विशेष पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) विजय बाली ने भी बैठक में शिरकत की और संघ के कार्यों की समीक्षा की। मंच पर इनके अलावा राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत, राजस्थान फुटबॉल महिला विंग की चेयरपर्सन रोशनी टांक और कोषाध्यक्ष कैलाश चंद्र खटीक ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और समस्त वार्षिक फुटबॉल गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।

चित्तौड़गढ़ संघ की रही सक्रिय भागीदारी

इस राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक में जिला फुटबॉल संघ, चित्तौड़गढ़ की ओर से भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई गई। चित्तौड़गढ़ जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष पूरण आंजना के विशेष निर्देशन में संघ के सेक्रेटरी फैसल खान ने बीकानेर पहुंचकर इस बैठक में हिस्सा लिया और जिले का प्रतिनिधित्व किया।

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने पर हुआ मंथन

बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों और जिला प्रतिनिधियों ने राजस्थान में फुटबॉल के स्तर को सुधारने और इसे देश में उच्च स्तरीय स्थान पर पहुंचाने के लिए कई अहम सुझाव दिए। चर्चा में मुख्य रूप से प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने, ग्रासरूट लेवल (निचले स्तर) पर नई प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें तराशने के लिए जोर दिया गया। सभी ने एक सुर में राजस्थान फुटबॉल को राष्ट्रीय पटल पर एक नई और मजबूत पहचान दिलाने का संकल्प लिया।

नवनियुक्त एनएसयूआई जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र सांखला का स्वागत

स्मार्ट हलचल

ब्यावर। माली-सैनी समाज जिला ब्यावर के समस्त बास एवं ढाणी अध्यक्षों द्वारा नवनियुक्त एनएसयूआई जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र सांखला का पुष्पमाला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर समाज के युवाओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि एक सक्रिय कार्यकर्ता को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से पूरे समाज में खुशी की लहर है। समाज के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठजनों ने कांग्रेस व ह्स्ढ्ढ के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सांखला की नियुक्ति युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। वे अपने दायित्व का पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ निर्वहन करते हुए छात्र हितों और समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे।

माली समाज के जिला अध्यक्ष रामदेव जी सोलंकी ने कहा कि समाज हमेशा प्रतिभाशाली एवं कर्मठ युवाओं के साथ खड़ा है। उन्हें पूरा विश्वास है कि शैलेन्द्र सांखला अपने नेतृत्व से संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

यह रहे उपस्थित:

इस गरिमामयी कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रामदेव जी सोलंकी, मोहनलाल दगदी (बड़ा बास अध्यक्ष), कैलाश गहलोत, सत्यनारायण पालड़िया, मुकेश सोलंकी, करण गहलोत, श्यामलाल पंच, मनोज सांखला, टिकमचंद माली, रामेश्वर बर, ओगड़राम गिरी, गोपाल गहलोत, मानक चौहान, सोहनलाल चौहान, मोतीलाल चौहान सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सांखला के उज्ज्वल भविष्य और सफल कार्यकाल की कामना की।

कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन की 231वीं जयंती पर सेवादल ने दी श्रद्धांजलि

स्मार्ट हलचल

ब्यावर। ब्यावर जिले के संस्थापक कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्शन की 231वीं जन्म जयंती के अवसर पर ब्यावर जिला कांग्रेस सेवादल द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्यावर सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष डॉ. अरविंद माथुर के नेतृत्व में छावनी फाटक बाहर स्थित डिक्सन साहब की मजार पर यह कार्यक्रम बेहद सादगी और गरिमा के साथ आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और

पदाधिकारियों ने कर्नल डिक्सन की मजार पर पुष्प मालाएं अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर ब्यावर जिले की खुशहाली, तरक्की और शहर में आपसी अमन-चैन व शांति कायम रहने के लिए विशेष प्रार्थना की गई। कार्यकर्ताओं ने डिक्सन साहब के आदर्शों को सदैव जीवित रखने का संकल्प लेते हुए 'जब तक सूरज चांद रहेगा, डिक्सन साहिब का नाम रहेगा' और 'डिक्सन साहिब अमर रहे' के गगनभेदी नारे भी लगाए।

इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस और विभिन्न संगठनों के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे:

पीसीसी सचिवः कल्पना भटनागर,जिला प्रवक्ताः सोहन मेवाड़ा,इंटक फेडरेशन प्रदेश अध्यक्षः एडवोकेट रामेश्वर मेवाड़ा,शिक्षक प्रकोष्ठ उपाध्यक्षः जगदीश सिंह राठौर,अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश कॉर्डिनेटरः ऋषि लाम्बा,सेवादल उपाध्यक्ष व पूर्व अध्यक्षः बाबू लाल पंवार एवं बालूराम सेन,कर्मचारी नेताः राम लाल लखन व अशोक मूंदड़ा,सेवादल ब्लॉक प्रवक्ताः भरत भाटी इसके साथ ही छगन मेवाड़ा, राहुल मेवाड़ा, आर्यन मैसी सहित कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस मौके पर डिक्सन साहब को याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित रहे।

राम मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष जांच हो : पूर्व विधायक जाड़ावत

स्मार्ट हलचल

शंभूपुरा। पूर्व राज्यमंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े समाचारों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि एसआईटी की रिपोर्ट में चढ़ावे के हिसाब-किताब, ऑडिट और प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं तो इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए तथा जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

जाड़ावत ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने घर-घर जाकर चंदा दिया था। साथ ही विभिन्न स्तरों पर सरकारी संसाधनों का भी उपयोग हुआ। ऐसे में मंदिर से जुड़े प्रत्येक रुपये का हिसाब जनता और श्रद्धालुओं के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंपत राय एवं अन्य जिन लोगों को मंदिर प्रबंधन और चढ़ावे की जिम्मेदारी सौंपी गई, उनके नाम यदि जांच रिपोर्टों में सामने आ रहे हैं तो यह अत्यंत गंभीर विषय है क्योंकि अभी और खुलासे के बाद बड़े नाम आने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 और 2024 के चुनावों में भाजपा ने भगवान राम के नाम पर व्यापक राजनीतिक प्रचार किया। पूरे देश में 'जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे' जैसे गीत और नारों के माध्यम से वोट मांगे गए। भाजपा ने राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर जनता से समर्थन प्राप्त किया, लेकिन आज यदि उसी राम मंदिर के चढ़ावे और प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो देशवासियों की भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है।

एक शाखा एक गांव में अभिरूचि एवं बाल संस्कार शिविर का समापन

स्मार्ट हलचल

बिजयनगर। भारत विकास परिषद् मुख्य शाखा बिजयनगर द्वारा फैथ एकेडमी माध्यमिक विद्यालय, संजयनगर बरल-द्वितीय में आयोजित 'एक शाखा एक गांव' अभिरूचि एवं बाल संस्कार शिविर का मंगलवार को समापन समारोह आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन 24 जून से 30 जून 2026 तक किया गया।

समापन समारोह में कोगटा फाउंडेशन जयपुर के बालमुकुंद कोगटा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदेमातरम् गायन के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष ज्ञानचंद नाहर ने की, जबकि संस्कार संयोजक लक्ष्मण लाल शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे।

शिविर में मेहंदी, योग, नृत्य, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग एवं कैलिग्राफी सहित विभिन्न विधाओं में कुल 187 बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सभी प्रतिभागी बच्चों को कॉपियां एवं पेन वितरित किए गए।

इस अवसर पर शिविर प्रभारी सरिता जैन, सहप्रभारी रेखा भंसाली, सचिव विमल कोठारी, वित्त सचिव पंकज पीपाड़ा, एक शाखा एक गांव प्रभारी एस.एन. जोशी, एस.एस. चौधरी, विमल भंसाली, बालमुकुंद जागेटिया, शाहबशरण जे. आचार्य, बुद्धि प्रकाश पारीक, अनिल कुमट, महिला सहभागिता संयोजक रेखा पोखरणा, मधु कोगटा, लेखा आचार्य, अंकिता धनोपिया सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

शिविर में नीलम सोनी, आरती अरोड़ा, ऐश्वर्या जैन एवं प्रियंका कुमावत ने प्रशिक्षण प्रदान किया। विद्यालय स्टाफ से अनिता जैन, रीतु शर्मा, संजू शर्मा, ललिता टेलर एवं सुनीता चौहान भी मौजूद रहीं। अंत में शाखा सचिव ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान में छात्राओं ने निभाई भूमिका

स्मार्ट हलचल

बिजयनगर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिजयनगर (ब्यावर) की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की स्वयंसेविकाओं एवं स्काउट-गाइड की छात्राओं ने 28 से 30 जून 2026 तक आयोजित तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए सामाजिक सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी श्रीमती कल्पना सिंह ने बताया कि अभियान में भाग लेने वाली छात्राओं को 27 जून को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। प्रशिक्षण के बाद छात्राओं ने तीन दिनों तक पल्स पोलियो बूथों पर सेवाएं देने के साथ-साथ घर-घर सर्वे कर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस सामाजिक सेवा कार्य में एनएसएस प्रभारी कल्पना सिंह, स्काउट-गाइड प्रभारी देंउ भील, स्वयंसेविकाएं कृष्णा सेन, दीपिका गुर्जर, अनुराधा शर्मा, अंजलि सेन तथा गाइड छात्राएं चंचल गुर्जर एवं ज्योति गुर्जर ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

गेणोली में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजितः एसडीएम ने सुनीं समस्याएं, 5 बुजुर्गों की पेंशन हुई बहाल

स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्राप्त हुए आवेदन, महिला बाल विकास विभाग ने मौके पर किया समस्याओं का समाधान

स्मार्ट हलचल

मांडलगढ़। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गेणोली में मंगलवार को राज्य सरकार के मंशानुरूप एकदिवसीय ग्रामीण सेवा शिविर का सफ़ल आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ-साथ राजस्थान सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामवासियों को दी गई। शिविर में ऑन-द-स्पॉट कई मामलों का निपटारा होने से ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का सीधा अवसर मिला।

तकनीकी खामी से रुकी 5 पेंशन धारकों की पेंशन हुई री-ओपनः

शिविर के दौरान ग्राम पंचायत प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़ी राहत प्रदान की। लंबे समय से पेंशन बंद होने के कारण परेशान चल रहे पांच पात्र पेंशनधारियों की पेंशन को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर मौके पर ही री-ओपन (बहाल) किया गया, जिससे बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे। इसके साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत नवीन शौचालयों के निर्माण

और प्रोत्साहन राशि के लिए कई ग्रामीणों से आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भावस्था के पोषण को रेखांकित करने वाली पारंपरिक 'महिला गोद भराई' रस्म का आयोजन किया गया और विभाग से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया गया।

दोपहर बाद स्थरू स्वाति झा ने किया औचक निरीक्षणः

शिविर में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जांचने और आमजन को मिल रही सुविधाओं की धरातलीय समीक्षा करने के लिए दोपहर 12:00 बजे बाद मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी (स्थरू) स्वाति झा मौके पर पहुंचीं। उन्होंने शिविर में लगी सभी विभागीय स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण किया और उपस्थित ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी परिवेदनाएं व स्थानीय समस्याएं सुनीं। एसडीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

इस सुअवसर पर मांडलगढ़ विकास अधिकारी हरिराम विजयवर्गीय, ग्राम विकास अधिकारी मुकुल ऐरन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, वार्ड पंच एवं भारी संख्या में गेणोली पंचायत के ग्रामवासी मौजूद रहे।

विश्व सोशल मीडिया दिवस पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले- लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका आज सबसे प्रभावशाली

डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता पर दिया जोर, अरावली बचाओ अभियान और पूर्व सरकार की डिजिटल नीति का किया उल्लेख

स्मार्ट हलचल

जयपुर। विश्व सोशल मीडिया दिवस के अवसर पर मंगलवार को जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया की भूमिका, लोकतंत्र, डिजिटल पत्रकारिता और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए डिजिटल मीडिया पत्रकार, सोशल मीडिया कंटेंट निर्माता, जनप्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्धजन मौजूद रहे।

अपने संबोधन में अशोक गहलोत ने कहा कि आज के राजनीतिक माहौल में सोशल मीडिया की भूमिका बेहद प्रभावशाली हो चुकी है। सीमित संसाधनों के बावजूद अनेक डिजिटल पत्रकार और कंटेंट निर्माता साहस और ईमानदारी के साथ जनहित के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का कार्य लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत का उदाहरण देते हुए अरावली बचाओ अभियान का उल्लेख किया। गहलोत ने कहा कि इस अभियान को सोशल मीडिया पर इतना व्यापक जनसमर्थन मिला कि मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया और अंततः उच्चतम न्यायालय को अपने ही एक फैसले पर रोक लगानी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह सोशल मीडिया की जनशक्ति का बड़ा उदाहरण है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े मुद्दे का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस विषय को मुख्य रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने लाया जा रहा है और अनेक लोग इस पर अपनी बात रख रहे हैं।

गहलोत ने अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई डिजिटल मीडिया नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि डिजिटल पत्रकारों और कंटेंट निर्माताओं के हितों को ध्यान में रखकर यह नीति तैयार की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार बदल गई, जिससे उस नीति का लाभ अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया को संस्थागत मजबूती देना समय की आवश्यकता है।

उन्होंने सभी डिजिटल पत्रकारों और कंटेंट निर्माताओं से कहा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी पूंजी विश्वसनीयता है। यदि तथ्यों पर आधारित और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य किया जाएगा तो जनता का विश्वास हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग समाज और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होना चाहिए।

देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर टिप्पणी करते हुए गहलोत ने राजनीतिक मूल्यों में गिरावट और जनप्रतिनिधियों की कथित खरीद-फरोख्त पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनादेश और संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनहित के मुद्दे उठाने वाले सोशल मीडिया मंचों तथा डिजिटल पत्रकारों के साथ उनका समर्थन हमेशा रहेगा।

कार्यक्रम के दौरान गहलोत के सोशल मीडिया अभियानों, जिनमें इंतजार शास्त्र और अरावली बचाओ जैसे अभियान शामिल रहे, उन पर आधारित एक प्रस्तुति भी दिखाई गई। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट निर्माताओं का आभार व्यक्त किया गया।

पोकलेन ठीक करने के बाद रुपए मांगे तो दो भाइयों, भांजे को बंधक बनाया, डंडों व लोहे के पाइप से पीटा

झूठा गांव का मामला आरोप-रातभर पीटकर सुबह सड़क पर छोड़ा, बंदूक दिखा मारने की धमकी दी

स्मार्ट हलचल

ब्यावर। जिले के रायपुर तहसील के बर गांव के रहने वाले एक मैकेनिक और उनके परिजनों के साथ बेरहमी से मारपीट, अपहरण और धार्मिक प्रताड़ना का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें रातभर बंधक बनाकर पीटा, बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और जबरन धार्मिक नारे लगवाए। बर निवासी पीड़ित 40 वर्षीय साजिद खान ने बताया कि ब्यावर रोड पर आर.के. फरीदाबाद नाम से दुकान चलाता है। उसने बताया कि 28 जून को रातडिया निवासी मानसिंह ने उन्हें फोन कर झूठा गांव स्थित मुकेश माली की माइंस पर पोकलेन मशीन ठीक करने के लिए बुलाया था। साजिद अपने भाई जुनैद और भांजे साहिल के साथ काम करने गया। रात करीब 1 बजे काम पूरा होने पर जब उन्होंने अपने पैसों की मांग की तो मानसिंह ने सुबह हिसाब करने की बात कही। जब वह जाने लगे तो मुकेश माली ने उन्हें रोका और अगवा कर ले गया। मारपीट की। इधर, देररात साहिल और जुनैद को अमृतकौर अस्पताल में भर्ती कराया गया

कार में आए हमलावर, ऑफिस में बनाया बंधक

शिकायत के अनुसार जब तीनों वापस लौटने लगे, तभी मुकेश माली अपने साथ 4-5 अन्य लोगों को फॉरच्यूनर कार में लेकर वहां पहुंचा। आरोप है कि तीनों को जबरन कार में डालकर मुकेश माली के ऑफिस ले गए। वहां तीनों को रस्सियों से बांधकर बंधक बना लिया गया।

पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने जातिसूचक और धार्मिक रूप से प्रताड़ित करते हुए नारे लगवाए। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत में बताया है कि आरोपियों ने बंदूक दिखाकर लोहे के पाइप, फावड़े के डंडे से पूरी रात बेरहमी से मारपीट की। मारपीट के दौरान जुनैद के बाल खींचकर उखाड़ दिए गए, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा।

मोबाइल तोड़े और अधमरा कर छोड़ाः आरोपियों ने तीनों पीडितों के मोबाइल छीनकर तोड़ दिए, जिसकी कीमत करीब 60 हजार रुपए है। सुबह तीनों को अधमरी हालत में छोड़ा गया। पीड़ित साजिद खान ने सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट पेश कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और घायलों का तुरंत मेडिकल कराने की गुहार लगाई है।

गुरु हरगोबिन्द साहिब जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाया

पंज पियाले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरु भारी । अर्जन काया पलट के, मूरत हरगोबिन्द सवारी ।।

स्मार्ट हलचल

भवानी मंडी। सिक्खों के छठे गुरु, मीरी-पीरी के मालिक, साहिब श्री गुरु हरगोबिन्द साहिब जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व को भवानी मंडी में बड़ी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा साहिब में आयोजित विशेष धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में संगत ने शिरकत की और गुरु साहिब के चरणों में नत्मस्तक होकर सेवा का अवसर प्राप्त किया।

गुरु हरगोबिन्द साहिब जी का जीवन साहस, न्याय और धर्म रक्षा का प्रतीक है। मात्र 11 वर्ष की आयु में गुरगद्दी संभालने के बाद उन्होंने सिक्ख पंथ को आध्यात्मिक (पीरी) के साथ-साथ शौर्य और सामरिक शक्ति (मीरी) प्रदान की। उन्होंने सिक्खों के सर्वोच्च स्थान अकाल तख्त साहिब की स्थापना की, दो तलवारें (मीरी-पीरी) धारण कीं और सिक्खों को 'संत-सिपाही' बनाने की परंपरा स्थापित की। उनके नेतृत्व में सिक्ख पंथ ने पहली बार मुगल अत्याचार के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध किया, जिसकी प्रेरणा आज भी लाखों अनुयायियों को सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करती है।

प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में दिनांक 18 जून से 29 जून तक श्री सुखमनी साहिब जी का लड़ीवार पाठ अनवरत रूप से चलाया गया। आज 30 जून को सवेरे 10.30 बजे निशान साहिब के चोले की सेवा और श्री सप्ताह पाठ साहिब की समाप्ति गुरु सिख परिवार की तरफ से हुई। इस अवसर पर विद्यार्थियों एवं युवाओं को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रीतपाल सिंह जी तथा पूर्व अध्यक्ष सरदार दर्शन सिंह द्वारा सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरुद्वारा साहिब के सचिव अमनदीप सिंह जी ने कहा कि गुरु हरगोबिन्द साहिब जी ने न केवल सिक्खों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया, बल्कि अन्याय के सामने सिर झुकाने से इंकार कर मानवता, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की प्रेरणा भी दी।

इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में भव्य दीवान सजाया गया। हजूरी रागी भाई बलबीर सिंह जी एवं भाई हरकीरत सिंह जी के जत्थे द्वारा गुरबाणी के शब्द-कीर्तन, नाम-बाणी एवं कथा-कीर्तन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का समापन 'सर्वत के भले' की अरदास के साथ हुआ। इसके पश्चात् मिस्सी रोटी और प्याज के साथ विशेष अटूट लंगर का प्रसाद संगत को वितरित किया गया।

भवानी मंडी एवं आसपास के क्षेत्रों की सिक्ख, सिंधी, पंजाबी तथा गुरु नानक नाम लेवा संगत ने पूरे कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न सेवा कार्यों में अपना योगदान दिया।

जिला कारागृह का उच्च स्तरीय निरीक्षणः हुई व्यापक समीक्षा

स्मार्ट हलचल

ब्यावर। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय सुकन्या शांता बनाम भारत संघ के तहत पारित आदेशों की पालना में ब्यावर जिला कारागृह का एक उच्च स्तरीय और विस्तृत निरीक्षण किया गया। गठित 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स कमेटी' के निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश (हारून) तथा जिला कलेक्टर (कमल राम मीणा) ने संयुक्त रूप से जेल परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान बंदियों की समस्याओं, उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और उनके मौलिक अधिकारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा की गई।

संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा पर विशेष ध्यान

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप बंदियों से सीधे बातचीत की। उनसे मुख्य रूप से यह जानकारी ली गई कि कारागृह के भीतर उनके साथ जाति, धर्म, समुदाय अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों ने जेल में बंदियों के सम्मान, सुरक्षा और उनके संवैधानिक अधिकारों की वर्तमान स्थिति को परखा।

मूलभूत सुविधाओं और विधिक सहायता का जायजा

प्रशासनिक और न्यायिक टीम ने जेल की बैरकों का अवलोकन करते हुए बंदियों के विचाराधीन मामलों की स्थिति जानी। संवाद के दौरान बंदियों से पूछा गया कि उन्हें अपने मुकदमों की पैरवी करने या कानूनी सहायता (लीगल एड) प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। इसके साथ ही, कारागृह परिसर में: भोजन व्यवस्था और स्वच्छताः रसोई और भोजन की गुणवत्ता तथा परिसर की साफ-सफाई को देखा गया। स्वास्थ्य सेवाएं: बंदियों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की समीक्षा की गई। सुधारात्मक गतिविधियां: कैदियों के कौशल विकास और पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया गया।

'जेल केवल दंड का स्थान नहीं, सुधार का केंद्र है'

निरीक्षण के अंत में अधिकारियों ने संबंधित कारागृह प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि बंदियों के मानवाधिकारों की हर हाल में रक्षा की जाए और उन्हें मानवीय गरिमा के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं। अधिकारियों ने संदेश दिया किः 'कारागृह केवल दंड देने का स्थान नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के सुधार और उनके पुनर्वास का केंद्र भी है। प्रत्येक बंदी के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। '

निरीक्षण टीम में ये रहे उपस्थित

इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें: न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारीः सोनल पारीख (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अपर जिला न्यायाधीश), ब्रह्मालाल जाट (अतिरिक्त जिला कलेक्टर), अनिता शर्मा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), और समिति सदस्य रेणु गर्ग। पुलिस एवं चिकित्सा विभागः डॉ. अनुकृति उज्जैनिया (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) और संजय सिंह गहलोत (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) । कारागृह प्रशासनः कोमल पुरोहित (उपाधीक्षक, जिला कारागृह ब्यावर), धारा सिंह (जेलर), तथा हनुमान सिंह राठौड़ (चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल)।

इस्लामिक नॉलेज टेस्ट-2026 के विजेताओं को मिले पुरस्कार

स्मार्ट हलचल | कोटा

विद्यार्थियों में ज्ञान, नैतिक मूल्यों और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस्लामिक नॉलेज टेस्ट (आईकेटी)-2026 के विजेताओं का सम्मान समारोह सोमवार को नयापुरा स्थित शेर वाले बाबा परिसर में आयोजित किया गया। जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द की छात्र इकाई स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसआईओ) कोटा यूनिट द्वारा आयोजित समारोह में करीब 300 लोगों ने भाग लिया।

गौरतलब है कि गत 10 मई को आयोजित इस्लामिक नॉलेज टेस्ट-2026 का आयोजन कोटा शहर के पांच परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 300 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

पुरस्कार वितरण समारोह में प्रत्येक वर्ग के शीर्ष 10 प्रतिभागियों को ट्रॉफी, मेडल, प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र देकर उनकी भागीदारी का सम्मान किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि शहर काजी जनाब जुबैर अहमद रहे। विशिष्ट अतिथियों में एसआईओ के पूर्व जोनल अध्यक्ष जनाब आसिम खान, जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, कोटा के अमीर-ए-मुकामी इंजीनियर अब्दुल कुद्दूस, जोनल सेक्रेटरी जनाब मुत्तालिब मिर्जा तथा असिस्टेंट जोनल सेक्रेटरी जनाब गुलशेर अहमद शामिल रहे। अतिथियों ने प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए शिक्षा, चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों के महत्व पर बल दिया तथा विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन और समाजोपयोगी कार्यों में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के समापन पर स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, कोटा यूनिट के अध्यक्ष अबू तल्हा ने सभी प्रतिभागियों, अभिभावकों, अतिथियों, जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, कोटा यूनिट तथा आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी स्वयंसेवकों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रसंत भारत गौरव मनोज्ञानाचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के ससंघ मंगल विहार आगमन पर पूरन आंजना परिवार ने किया भव्य स्वागत

पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की ओर से आंजना परिवारजनों ने किया आत्मीय अभिनंदन, धर्म एवं संस्कारों के संरक्षण का लिया संदेश

स्मार्ट हलचल | निंबाहेड़ा

निंबाहेड़ा की पुण्य धरा पर राष्ट्रसंत, भारत गौरव, प्रख्यात जैनाचार्य मनोज्ञानाचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज के ससंघ मंगल विहार आगमन पर श्रद्धा, भक्ति एवं आध्यात्मिक उल्लास का अनुपम वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की ओर से उनके परिवारजनों ने छोटीसादड़ी निंबाहेड़ा मार्ग पर स्थित 100 बीघा फार्म हाउस पर पहुँचकर आचार्य श्री का आत्मीय स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन किया तथा उनके पावन सान्निध्य में धर्मोपदेश एवं आशीर्वाद प्राप्त किया।

इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष एवं युवा उद्योगपति पूरन आंजना ने अपने परिवार सहित राष्ट्रसंत श्री पुलक सागर जी महाराज के चरणों में श्रद्धा निवेदित करते हुए उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि संतों का सान्निध्य समाज को नई दिशा प्रदान करता है तथा उनके आशीर्वचन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं।

आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मानव जीवन में धर्म, संयम, संस्कार, सदाचार एवं सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जीवन की वास्तविक समृद्धि भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, सद्भावना एवं परोपकार की भावना में निहित है। संतों के सान्निध्य से मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध होता है तथा समाज में नैतिक मूल्यों का संरक्षण संभव हो पाता है।

निंबाहेड़ा में मंगल विहार आगमन के दौरान श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आचार्य श्री के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वातावरण धार्मिक भावनाओं, श्रद्धा एवं भक्ति से सराबोर रहा। श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री के चरणों में नमन कर परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सुख-समृद्धि तथा कल्याण की कामना की।

इस अवसर पर निंबाहेड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष गोपाल आंजना, विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष जसवंत सिंह आंजना, वरिष्ठ पत्रकार मनोज सोनी,नितेश आंजना, विक्रम आंजना, महावीर जैन, आशुतोष टांक एवं विष्णुलाल मीणा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने आचार्य श्री का स्वागत-अभिनंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

देशभर में कोटा विश्वविद्यालय को मिली विशिष्ट पहचान, उज्बेकिस्तान की सिल्क रोड यूनिवर्सिटी ने चुना एकमात्र भारतीय संस्थान

5 पूर्ण छात्रवृत्तियों पर होगा चयन, कुलगुरु प्रो. बी.पी. सारस्वत ने बताया अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की दिशा में बड़ी उपलब्धि

स्मार्ट हलचल | कोटा

पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत शिक्षा के क्षेत्र में कोटा विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। उज्बेकिस्तान के समरकंद स्थित सिल्क रोड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पूरे भारत में केवल कोटा विश्वविद्यालय को अपने साझेदार संस्थान के रूप में चयनित किया है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. (डॉ.) बी.पी. सारस्वत के मार्गदर्शन तथा पर्यटन एवं आतिथ्य विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) अनुकृति शर्मा के प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है।

विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति (प्रशासन) डी. नसीमोव ने प्रो. (डॉ.) अनुकृति शर्मा को भेजे आधिकारिक पत्र में भारतीय विद्यार्थियों एवं स्नातकों के बीच इस अवसर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा इच्छुक अभ्यर्थियों के चयन में सहयोग का अनुरोध किया है। भारत के विद्यार्थियों के लिए पांच पूर्ण ग्रांट आधारित छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई गई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2026 है तथा नया शैक्षणिक सत्र सितंबर से प्रारंभ होगा।

कुलगुरु प्रो. (डॉ.) बी.पी. सारस्वत ने कहा कि यह उपलब्धि कोटा विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय साख, शैक्षणिक गुणवत्ता और वैश्विक सहयोग की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को वैश्विक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शिक्षा, शोध, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने अधिकाधिक विद्यार्थियों से इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया।

प्रो. (डॉ.) अनुकृति शर्मा ने बताया कि पर्यटन एवं प्रबंधन सहित संबंधित विषयों के प्रति विद्यार्थियों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 500 अमेरिकी डॉलर छात्रवृत्ति, 100 अमेरिकी डॉलर प्रतिमाह छात्रावास व्यय के लिए, भारत-उज्बेकिस्तान आने-जाने हेतु इकोनॉमी क्लास का निःशुल्क हवाई टिकट तथा उज्बेकिस्तान की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराने के लिए वर्ष में दो अध्ययन यात्राएं कराई जाएंगी। प्रत्येक अध्ययन यात्रा के लिए 100 अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि चयनित विद्यार्थी पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन, पुरातत्व, कला एवं स्थापत्य स्मारकों की बहाली, संग्रहालय विज्ञान, संरक्षण तथा ऐतिहासिक धरोहरों के रखरखाव जैसे विषयों में मास्टर डिग्री प्राप्त करेंगे। यह छात्रवृत्ति योजना उज्बेकिस्तान सरकार की अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग नीति के तहत संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक सहयोग और वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना है।

योग दिवस आयोजन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों एवं स्वयंसेवकों का हुआ सम्मान

राजस्थान में बूंदी ने प्राप्त किया तृतीय स्थान, जिला कलेक्टर ने इसे सामूहिक जनभागीदारी की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया

स्मार्ट हलचल | बूंदी

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के उपरांत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बालचंदपाड़ा में योग दिवस आयोजन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों, सामाजिक संगठनों, योग प्रशिक्षकों एवं स्वयंसेवकों के सम्मान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव रहे, अध्यक्षता संभागीय अतिरिक्त निदेशक डॉ अंजना शर्मा × विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीएम (सिलिंग) रमेश देव , आयुर्वेद उपनिदेशक डॉ मालती पारीक, आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य डॉ नित्यानंद शर्मा , कानूनी चिकित्सक डॉ गौरव चतुर्वेदी उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ, अनुशासित एवं संतुलित जीवन जीने की भारतीय जीवन-पद्धति है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बूंदी जिले में प्रशासन, आयुर्वेद विभाग, विभिन्न संस्थाओं, स्वयंसेवकों एवं आमजन की सक्रिय भागीदारी से योग को जन-आंदोलन का स्वरूप मिला। इसी सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन में बूंदी जिले ने पूरे राजस्थान में तृतीय स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जो जिले के लिए गर्व का विषय है। आयोजन प्रभारी × जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी के पीएमओ डॉ सुनील कुशवाह ने 50 दिवसीय योग दिवस काउंटडाउन ,ग्राम, ब्लॉक × जिला स्तर पर आयोजित हुए कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी।

समारोह में योग दिवस के सफल आयोजन में उल्लेखनीय सहयोग देने वाले संस्थानों, योग प्रशिक्षकों, सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवकों को प्रशस्ति-पत्र एवं सम्मान देकर उनके योगदान का अभिनंदन किया गया। जिला कलेक्टर ने सभी सम्मानितजनों से भविष्य में भी योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों में सक्रिय सहभागिता बनाए रखने का आह्वान किया।इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने निरोगी जीवन के लिए आयुर्वेद में बताई गई स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आव्हान किया। कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य केंद्रों के प्रभारियों,टीम योग फॉर निरोगी बूंदी,गणेश व्यायामशाला के योग शिविर प्रभारी दिनेश कुमार, उत्कर्ष चौहान,लोकेंद्र,श्रीजी योगशाला निदेशक दीपक गुर्जर, भूपेन्द्र योगी, प्रांशु सिंह, विशाल गुर्जर, हार्टफुलनेस से चांदनी वरयानी, डॉ. सरला कुशवाह, पूजा खत्री, सुधा चौधरी, चारु अग्रवाल, पंकज पारीक, रविंद्र गुर्जर, चंचल कुमावत,स्वच्छता सेवकों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया।इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, योग प्रशिक्षक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे। अंत में सभी ने योग को नियमित जीवनचर्या का हिस्सा बनाने तथा स्वस्थ, निरोगी एवं जागरूक समाज के निर्माण में निरंतर सहयोग देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने इस माह सेवानिवृत्ति हो रही आयुर्वेद उपनिदेशक डॉ मालती पारीक × डॉ बृजमोहन सुमन का सम्मान भी किया।

वर्दी का वादा: संकट में परिवार के साथ खड़ी रहेगी पुलिस

सवाईमाधोपुर एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी की पहल पर शुरू हुआ 'अक्षय फंड', पुलिसकर्मी के आकस्मिक निधन पर परिजनों को तत्काल 3 लाख की सहायता

स्मार्ट हलचल| जयपुर

पुलिस की वर्दी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसके पीछे ऐसे हजारों परिवारों का विश्वास, त्याग और धैर्य भी जुड़ा होता है, जो हर दिन अपने प्रियजन को समाज की सुरक्षा के लिए समर्पित करते हैं। ऐसे में यदि किसी पुलिसकर्मी के साथ कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए तो सबसे बड़ा आघात उसके परिवार पर पड़ता है। इसी मानवीय संवेदना को केंद्र में रखते हुए सवाई माधोपुर की पुलिस अधीक्षक सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी ने पुलिस कल्याण की दिशा में एक ऐसी पहल की है, जो संवेदनशील पुलिसिंग का प्रेरक उदाहरण बनकर उभरी है। उनके नेतृत्व में शुरू किया गया 'अक्षय फंड' अब संकट की घड़ी में पुलिस परिवारों के लिए एक मजबूत आर्थिक संबल बनेगा।

एक संवेदनशील सोच से मिली नई शुरुआत

पुलिस संगठन अपने कर्मियों को केवल सहकर्मी नहीं, बल्कि एक परिवार मानता है। इसी भावना को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'अक्षय फंड' की स्थापना की गई है। यह

पहल इस विश्वास को मजबूत करती है कि पुलिसकर्मी चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, उनका परिवार कभी अकेला नहीं रहेगा।

कांस्टेबल कुंजीलाल की स्मृति से जन्मी पहल

एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने बताया कि हाल ही में सवाई माधोपुर पुलिस लाइन में कार्यरत कांस्टेबल श्री कुंजीलाल के आकस्मिक निधन ने पूरे पुलिस परिवार को भावुक कर दिया। इस घटना ने यह आवश्यकता महसूस कराई कि ऐसी परिस्थितियों में पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक स्थायी और व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए। इसी विचार ने 'अक्षय फंड' का स्वरूप लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में लगभग 1400 पुलिसकर्मी कार्यरत है और अनुमानतः 16 लाख रुपया इस फंड में एकत्र हो सकता है।

साथियों के सहयोग से तैयार होगा सुरक्षा कवच

एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी की पहल पर सवाई माधोपुर जिला पुलिस के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के स्वैच्छिक अंशदान से इस फंड का गठन किया जाएगा। यह केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि अपने साथी और उसके परिवार के प्रति अपनत्व, उत्तरदायित्व और एकजुटता का जीवंत उदाहरण है।

संकट की घड़ी में मिलेगा तत्काल सहारा

'अक्षय फंड' के माध्यम से यदि किसी पुलिसकर्मी का आकस्मिक निधन होता है, तो उसके परिजनों को 3 लाख की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता शोकाकुल परिवार को कठिन समय में प्रारंभिक आर्थिक राहत प्रदान करेगी और उन्हें यह भरोसा दिलाएगी कि उनका पुलिस परिवार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है।

आत्मनिर्भर व्यवस्था, दीर्घकालिक सुरक्षा

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यावहारिक और आत्मनिर्भर कार्यप्रणाली है। फंड बनने के बाद जब तक उसकी राशि सहायता के रूप में उपयोग नहीं हो जाती, तब तक किसी भी कार्मिक के वेतन से पुनः कटौती नहीं की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर ही पुनः एक दिन के वेतन का स्वैच्छिक अंशदान लिया जाएगा। इससे योजना निरंतर चलती रहेगी और कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा।

पुलिस परिवारों में बढ़ेगा विश्वास और मनोबल

यह पहल केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस संगठन के भीतर विश्वास, आत्मीयता और पारिवारिक भावना को भी नई मजबूती प्रदान करेगी। इससे प्रत्येक पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन और अधिक निश्चिंत होकर कर सकेगा, क्योंकि उसे यह विश्वास रहेगा कि विपरीत परिस्थितियों में उसका परिवार अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

संवेदना, सहयोग और सामाजिक सुरक्षा का संगम

'अक्षय फंड' पुलिस संगठन की उस कार्यसंस्कृति का परिचायक है, जहाँ संवेदना और सहयोग केवल शब्द नहीं, बल्कि व्यवहार का हिस्सा हैं। यह पहल पुलिस कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और मानवीय मूल्यों का ऐसा संगम है, जो संगठन के भीतर आत्मविश्वास और पारस्परिक विश्वास को और अधिक मजबूत करेगा।

प्रदेशभर के लिए बन सकता है अनुकरणीय मॉडल

एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी की यह अभिनव पहल पुलिस महकमे में व्यापक सराहना का विषय बनी हुई है। यह केवल सवाई माधोपुर जिला पुलिस का कल्याणकारी प्रयास नहीं, बल्कि ऐसा मॉडल है जिसे भविष्य में राजस्थान के अन्य जिलों में भी अपनाया जा सकता है। यह पहल इस संदेश को सशक्त करती है कि खाकी केवल कानून की संरक्षक नहीं, बल्कि अपने परिवार की संवेदनाओं की भी सच्ची प्रहरी है।

कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया

स्मार्ट हलचल

सांगोद। सांगोद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटा बूंदी कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी वह पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का जन्मदिन केक काटकर जिला देहात कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष असरार अहमद के नेतृत्व में मनाया जिला देहात कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष असरार अहमद कांग्रेस नगर अध्यक्ष मनोज सुवालका वक्फ कमेटी सदर मिर्ज़ा मुश्ताक अहमद पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजेन्द्र गहलोत पुर्व सरपंच शिवराम मेहता फूलचंद गोचर जिला देहात अल्पसंख्यक प्रवक्ता मुसब्बिर खान जिला देहात अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष सलीम अंसारी निरंजन जैन सत्यनारायण मेहता ने बताया कि 30 जून को कोटा बुदी कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के जन्मदिन के अवसर पर सांगोंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा केक काटकर मनाया गया कांग्रेस पदाधिकारी वह कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रह्लाद गुंजल का जीवन संघर्ष,साहस,जनसमर्थन का प्रतीक,संघर्षशील व्यक्तित्व, मुखर वक्ता और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले प्रह्लाद गुंजल के जन्म दिवस पर समर्थकों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए 'प्रह्लाद जिंदाबाद' के नारों के साथ उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की समर्थकों ने कहा कि कोटा ही नहीं,पूरे राजस्थान में प्रह्लाद गुंजल की आवाज़ और संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। प्रह्लाद गुंजल अपनी रीढ़ की हड्डी की तरह अडिग रहने वाले, बेबाक और जनहित के मुद्दों पर मुखर आवाज़ उठाने वाले नेता हैं उनके जन्म दिन पर समर्थकों ने उनके उज्ज्वल भविष्य,उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर जनसेवा की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी । इस दौरान अंकुश शर्मा महमूद बेग बृजमोहन रेगर शौकत अंसारी ऋषिराज जादम असगर हुसैन चांद भाई नियारगीर शरीफ टेलर रफीक भाई मियारगीर निसार पठान रफीक ठेकेदार प्रभुलाल सुमन असलम अंसारी ज़ाकिर हुसैन शरीफ अंसारी सलामउद्दीन ताहिर अंसारी अज़हर अंसारी शाकिर टेलर महबूब मंसूरी रमाकांत कुशवाह रुस्तम अंसारी विजय वाल्मीकि जाफर हुसैन शहजाद खान जलाल मिर्जा अफरोज पठान अनीस अंसारी शोएब अंसारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सेवा, संस्कार और जनसमर्पण का प्रतीक बना बगरू विधायक कैलाश वर्मा का जन्मदिवस,15 हजार से अधिक लोग पहुंचे निमेड़ा

स्मार्ट हलचल

बगरू-जयपुर। बगरू विधायक एवं राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री कैलाश वर्मा का जन्मदिवस मंगलवार को उनके पैतृक गांव निमेड़ा स्थित श्री श्याम गौशाला में 'सेवा संकल्प दिवस' के रूप में श्रद्धा, उत्साह और जनभागीदारी के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर बगरू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से सरपंचों के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं समर्थक निमेड़ा पहुंचे। सभी ने कैलाश वर्मा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया।

जन्मदिन को मनाया सेवा दिवस के रूप में

जन्मदिवस पर कैलाश वर्मा ने दिन की शुरुआत जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन

एवं पूजा-अर्चना से की। इसके बाद पैतृक गांव निमेड़ा पहुंचकर इष्ट देवों के दर्शन किए तथा माता-पिता एवं परिवार के वरिष्ठजनों का आशीर्वाद लिया। श्री श्याम गौशाला में गौसेवा करते हुए गायों को हरा चारा एवं गुड़ खिलाया तथा स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। सेवा कार्यों की श्रृंखला में विधायक कोष से क्षेत्र के 15 दिव्यांगजनों को स्कूटियों का वितरण किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

श्रीमद्भागवत कथा में पहुंचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष

कैलाश वर्मा का जन्मोत्सव पिछले सात दिनों से 'सेवा संकल्प समारोह' के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान श्री श्याम गौशाला में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक वातावरण से ओत-प्रोत कर दिया। आयोजन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्य सरकार के अनेक मंत्री, सांसद, विधायक तथा गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। मंगलवार को आयोजित जन्मदिवस समारोह में 15 हजार से अधिक लोगों ने निमेड़ा पहुंचकर कैलाश वर्मा को शुभकामनाएं दीं। पूरे दिन श्री श्याम गौशाला परिसर जनसैलाब, सेवा, आध्यात्मिकता और जनसमर्पण का साक्षी बना।

जनसेवा ही प्रथम लक्ष्य : कैलाश वर्मा

बगरू विधायक ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि जनसेवा ही मेरा संकल्प है। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से सेवा के संकल्प को मजबूती मिलती है। कैलाश वर्मा वर्ष 2013 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे तथा वर्ष 2023 में पुनः बगरू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका संपूर्ण राजनीतिक जीवन जनसेवा, गौसेवा, राष्ट्रहित और समाज कल्याण को समर्पित रहा है।

प्युवा उद्यमियों के लिए आरएफसी का बड़ा अभियान, एक दिन में 10.36 करोड़ के ऋण आवेदन प्राप्त, 5.5% ब्याज पर 2 करोड़ तक की वित्तीय मदद

स्मार्ट हलचल

सांगानेर। राजस्थान में युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान वित्त निगम ने मंगलवार को जयपुर के सीतापुरा रीको परिसर में उद्योग प्रोत्साहन शिविर आयोजित किया। शिविर में बड़ी संख्या में उद्यमियों ने भाग लिया और निगम की विभिन्न ऋण योजनाओं में रुचि दिखाई। एक ही दिन में 10 करोड़ 36 लाख रुपये के ऋण आवेदन प्राप्त हुए।

राजस्थान वित्त निगम के कार्यकारी निदेशक डॉ हर सहाय मीणा ने बताया कि शिविर का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि नए उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराना और उन्हें वित्तीय सहायता तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। प्रतिभागियों को विभिन्न योजनाओं, पात्रता, ऋण प्रक्रिया और परियोजना तैयार करने से जुड़ी जानकारी भी दी गई।

उद्योग से लेकर अस्पताल और होटल तक मिलेगा वित्तीय सहयोग

निगम के अनुसार उद्योग, होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सेवा क्षेत्रों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित भूमि के विरुद्ध भी ऋण सुविधा दी जा रही है, जिससे निवेशकों को परियोजनाएं शुरू करने में आसानी होगी।

5.5% ब्याज पर 2 करोड़ तक का ऋण

महाप्रबंधक पंकज पुरोहित ने बताया कि युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र युवाओं को 5.50 प्रतिशत ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना युवाओं को रोजगार मांगने के बजाय रोजगार सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास है। कार्यकारी निदेशक डॉ हरसहाय मीणा ने कहा कि निगम प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उद्यमियों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। निगम की प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और उद्यमी हितैषी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम एनपीए कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि अधिक से अधिक संसाधन नए उद्योगों को वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराए जा सकें।

शिविर में मिले 10.36 करोड़ रुपये के ऋण आवेदन इस बात का संकेत हैं कि राजस्थान के युवा उद्यमियों का राजस्थान वित्त निगम की योजनाओं पर भरोसा बढ़ रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के उद्योग प्रोत्साहन शिविर नए निवेश को बढ़ावा देंगे और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे।

घाड़ में कार ने बाइक को टक्कर मारी, युवक की मौके पर मौत

स्मार्ट हलचल

घाड़ (देवली), टोंक। घाड़ थाना क्षेत्र के गैरोली मोड़ के पास नेशनल हाईवे 52 पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार 17 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई।

मृतक की पहचान धाकडियावास (कंवरपुरा) निवासी रामदयाल कुमावत के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, रामदयाल अपनी बाइक से गैरोली मोड़ के पास से गुजर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे की सूचना मिलते ही घाड़ पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई रणजीत मीणा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दूनी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, कार चालक की तलाश जारी है और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

राहोली में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित, ग्रामीणों को पट्टा वितरण सहित 22 विभागों की योजनाओं का मिला लाभ

स्मार्ट हलचल

राहोली। राज्य सरकार के जनकल्याण शिविरों के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन ग्राम पंचायत राहोली के भारत निर्माण सेवा केंद्र पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया। शिविर में 22 विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों ने उपस्थित रहकर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लाभ प्रदान किया। ग्राम विकास अधिकारी राकेश कुमार बैरवा ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा गुलाब चंद चावला, कमोज कंवर, नर नारायण शर्मा, सत्यनारायण, कल्याण सिंह सहित अन्य लोगों को आवासीय मकानों के

पट्टे प्रदान किए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि के लिए 10 आवेदन प्राप्त हुए।

राजस्व विभाग द्वारा धारा 136 के तहत 22 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण, नामांतरण, तकासमा सहित अन्य कार्य किए गए। घुमंतू परिवारों के लिए आबादी भूमि आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया गया।

शिक्षा विभाग द्वारा पालनहार योजना में 6 बच्चों को लाभान्वित किया गया तथा घुमंतू परिवारों के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश कराया गया। राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनाए गए।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट वितरित की गई। चिकित्सा विभाग ने शिविर में बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन की जांच, टीबी स्क्रीनिंग, बच्चों का टीकाकरण तथा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की। कृषि पर्यवेक्षक आशीष मीणा ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा योजनाओं की जानकारी के साथ तारबंदी और पाइपलाइन की पत्रावलियां तैयार की गईं। पशुपालन विभाग ने 10 पशुपालकों को मंगला पशु बीमा पॉलिसी का वितरण किया।

शिविर में प्रशासक फुला देवी मीणा, पीएम श्री प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह नरूका, मधुसूदन शर्मा, शंकर लाल अटल, वार्ड पंच मुकेश चावला, कन्हैया लाल चावला सहित ग्रामीणजन और अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

घाड़ में 22 विभागों ने सुनी जनसमस्याएं

विधायक और उपखंड अधिकारी ने मौके पर दिए निर्देश

स्मार्ट हलचल

घाड़ (देवली), टोंक। टोंक जिले के देवली उपखंड की ग्राम पंचायत घाड़ में 'ग्रामीण सेवा शिविर' का आयोजन किया गया। राज्य सरकार और जिला प्रशासन, टोंक के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में क्षेत्र के विकास और जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए 22 विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एक मंच पर उपस्थित रहे।

शिविर में देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर और देवली उपखंड अधिकारी रूबी अंसार ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए।

इस दौरान, राजीविका टीम द्वारा कई स्वयं सहायता समूहों को देवली उपखंड अधिकारी रूबी अंसार के माध्यम से चेक वितरित किए गए। शिविर में दूनी तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, घाड़ चिकित्सा अधिकारी डॉ. जितेंद्र कुमार वर्मा, सरपंच प्रियंका देवतवाल, पटवारी, गिरदावर सहित कई विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्व, पंचायती राज, विद्युत, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित कुल 22 विभागों ने अपने स्टॉल लगाए।

शिविर में किसानों ने अपने अवरुद्ध खेतों के रास्तों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण की समस्या उठाई। ग्रामीणों ने पेयजल की कमी और दौलतपुरा में गंदे पानी के जलभराव से हो रही परेशानी से भी अवगत कराया।

घाड़ कस्बे के मुख्य बस स्टैंड से दूनी रोड वाली विद्युत लाइन के जगह-जगह कटे होने और बार-बार लाइन फॉल्ट होने की शिकायत की गई, जिसके लिए नई केबल डलवाने हेतु विभाग के जैन संदीप श्रीवास्तव को अवगत कराया गया। घाड़ क्षेत्र में हो रहे बेखौफ अवैध खनन का मुद्दा भी विधायक राजेंद्र गुर्जर और उपखंड अधिकारी रूबी अंसार के सामने चर्चा का विषय रहा, जिस पर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए।

किसान दुर्गा शंकर देवतवाल ने अपने खेत के रास्ते को लेकर महीनों से चक्कर काटने की बात कही, लेकिन जाप्ता उपलब्ध न होने का बहाना बताया जाता रहा। शिविर में कानाराम मीणा दौलतपुरा, महावीर प्रसाद भाटी, विनोद साहू, रमेश देवतवाल, भरत मीणा, शंभू शर्मा, महावीर गुर्जर, राजेश भाट, अनिता मीणा, ममता सैनी सहित कई ग्रामीण व कर्मचारी उपस्थित थे।

अवैध शराब ब्रांच बंद कराने की मांग तेज, तीन दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो धरने की चेतावनी

महिलाओं समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, हाल ही में हुई मारपीट की घटना का भी दिया हवाला

स्मार्ट हलचल

सावर (अजमेर)। ग्राम पंचायत आमली के गांव मेहरूखुर्द एवं आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी सावर को ज्ञापन सौंपकर वर्षों से संचालित अवैध शराब ब्रांच को तत्काल बंद कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि तीन दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वे अवैध शराब ब्रांच के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि मेहरूखुर्द में लंबे समय से संचालित कथित अवैध शराब ब्रांच के कारण पूरे क्षेत्र का सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। यहां दिन-रात शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाओं, छात्राओं, राहगीरों एवं आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब के नशे में आए दिन गाली-गलौज, मारपीट, झगड़े और अन्य असामाजिक गतिविधियां होती रहती हैं, जिससे गांव का शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि समूह संख्या 283 के अंतर्गत आमली एवं गोरधा ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए केवल एक वैध शराब दुकान स्वीकृत है। इसके बावजूद मेहरूखुर्द में कथित रूप से अवैध शराब ब्रांच संचालित होना आबकारी नियमों का खुला उल्लंघन है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब यहां किसी वैध शराब दुकान की स्वीकृति नहीं है तो आखिर यह कारोबार किसके संरक्षण में चल रहा है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि यह अवैध शराब ब्रांच चार रास्तों के संगम (क्रॉसिंग) के निकट स्थित है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। नशे में धुत लोगों

के कारण सड़क पर अव्यवस्था का माहौल रहता है तथा दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्थान पर पहले भी कई छोटे-बड़े हादसे हो चुके हैं और भविष्य में बड़ी जनहानि की आशंका बनी हुई है।

ग्रामीणों ने बताया कि मेहरूखुर्द, किशनपुरा, माधोपुरा सहित आसपास के गांवों के छात्र-छात्राएं प्रतिदिन इसी मार्ग से मेहरूकलां स्थित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययन के लिए आते-जाते हैं। शराबियों की भीड़ और अभद्र व्यवहार के कारण छात्राओं एवं महिलाओं में भय का वातावरण बना रहता है। कई अभिभावकों ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है।

ग्रामीणों ने धार्मिक आस्था का भी हवाला देते हुए बताया कि मेहरूखुर्द स्थित भैरव धाम पर प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार, रविवार सहित अन्य दिनों में प्रदेश एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे धार्मिक स्थल के समीप कथित अवैध शराब बिक्री से क्षेत्र की छवि धूमिल हो रही है और श्रद्धालुओं में भी असंतोष है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि इस अवैध शराब ब्रांच के कारण युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है, जिससे कई परिवार आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक संकट का सामना कर रहे हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शराब की वजह से घरेलू कलह और पारिवारिक विवाद बढ़ रहे हैं तथा सामाजिक ताना-बाना कमजोर हो रहा है।

ग्रामीणों ने हाल ही में इसी अवैध शराब ब्रांच पर दो गुटों के बीच हुई मारपीट की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में और गंभीर घटनाएं हो सकती हैं।

ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने मांग की कि मेहरूखुर्द में संचालित कथित अवैध शराब ब्रांच की तत्काल जांच कर उसे स्थायी रूप से बंद कराया जाए, अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों एवं उनके संरक्षकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्षेत्र में पुलिस एवं आबकारी विभाग की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, विद्यार्थियों एवं महिलाओं की सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएं, भैरव धाम एवं आसपास के क्षेत्र को नशामुक्त क्षेत्र घोषित करने पर विचार किया जाए तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

इस दौरान देवीलाल, संतरा, प्रेम, सीता मीणा, बदाम, सुनीता, ललिता, गलकु, आशा, विमला, नंदू, पुष्पा देवी, सुशीला, सीमा, माया, लाली देवी, काली, अंजू सहित सैकड़ों ग्रामीण एवं बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

नागरिकता के दस्तावेजों पर इतना भ्रम ठीक नहीं..

उमेश चतुर्वेदी

आधुनिक विश्व व्यवस्था की एक खामी यह है कि यहां कानून की भाषा अलग होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कानूनी भाषा जटिल होती है और उसके शब्द जाल को आम आदमी नहीं समझ पाता। इसी आधार पर उसकी अवधारणाएं विकसित होती हैं और फिर वह किसी विषय का व्यवस्था को लेकर अपनी राय बनाता है।

पिछले कुछ वर्षों में पासपोर्ट हासिल करना आसान हो गया है। इसकी वजह तकनीकी क्रांति तो है ही, लेकिन सरकारी नीतियों ने भी आम आदमी के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया है। पासपोर्ट हासिल करने के कठिन दौर से लेकर आसानी से प्राप्त होने के मौजूदा दौर में, आम नागरिक इसे अपनी नागरिकता का एक वैध दस्तावेज मानता रहा है। लेकिन पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के पासपोर्ट को लेकर दिए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस अधिकारी के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा के लिए एक दस्तावेज है, भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं। जहां पासपोर्ट हासिल करने को चार धाम यात्रा जैसी उपलब्धि माना जाता रहा हो, जहां किसी व्यक्ति की पहचान के लिए मजबूत सरकारी दस्तावेज माना जाता रहा हो, वहां ऐसा बयान आएगा तो विवाद होगा ही। तो विवाद हो रहा है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट नागरिकता का वैध दस्तावेज नही है तो फिर कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता के लिए क्या सबूत पेश करे।

भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के शब्दों से गुजरें तो विदेश मंत्रालय के अधिकारी का कहना गलत भी नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में मतदाता सूचियों के विशेष और गहन परीक्षण के दौरान जब घोषित कर दिया गया कि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र होना उसकी नागरिकता के सबूत नहीं है और अब पासपोर्ट भी नहीं रहा, तो फिर भारतीय नागरिक क्या करे। जरूरत पड़ने पर वह कैसे साबित करे कि वह भारतीय नागरिक है। इस आधार पर तो देश के ज्यादातर लोग अपनी नागरिकता को तो साबित ही नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज के दौर की तमाम लड़ाइयों का बुनियादी और मजबूत आधार चूंकि नैरेटिव बन गया है तो यह भी साबित करने की कोशिश होगी कि मोदी सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है। इसके लपेटे में मोदी समर्थक ताकतें भी आएंगी, भारतीय जनता पार्टी पर तो खैर सवाल उठेगा ही। इस नैरेटिव को खड़ा होने से पहले ही जरूरी है कि नागरिकता के वैध दस्तावेज को लेकर जारी भ्रम को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अन्यथा भ्रम का यह कुहासा जितना फैलेगा, वह आम नागरिक के मन में व्यवस्था के प्रति गुस्सा और क्षोभ भरेगा। इससे तनाव बढ़ाने वाली ताकतों को भी मौका मिलेगा।

पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने जो कहा है, वह गलत भी नहीं है। अपने देश में भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जारी किया जाता है। जबकि भारत में नागरिकता की व्याख्या और प्रमाणिकता के लिए भारतीय नागरिकता कानून 1955 है। पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 के मुताबिक, अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है। बस शर्त यह होगी कि सरकार को ऐसा लगे कि उसके लिए पासपोर्ट जारी करना व्यापक जनहित में जरूरी है। इस कानून से साफ है कि पासपोर्ट और नागरिकता दो अलग अलग चीजें हैं। बेशक भारतीय पासपोर्ट सिर्फ भारतीयों को ही मिलता है, लेकिन यह पत्थर की लकीर जैसा नियम नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 20 भारत सरकार को छूट देती है कि व्यापक जनहित में वह भारतीय नागरिक ना होने के बावजूद किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी कर सकती है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारी के बयान पर भले ही विवाद खड़ा हुआ हो, लेकिन पासपोर्ट के जरिए नागरिकता प्रमाणित करने के तीन अभियुक्तों समेत चार लोगों के दावे को बांबे हाईकोर्ट 2013 में ही खारिज कर चुका है। उन्होंने अपनी नागरिकता के लिए पासपोर्ट पेश किया था। बांबे हाईकोर्ट ने दो सितंबर 2013 के अपने फैसले में साफ कर दिया था कि अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ है तो पासपोर्ट को अपनी नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं पेश कर सकते। वैसे आधार कार्ड का कानून भी मानता है कि आधार कार्ड सिर्फ निवास और पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। आधार कानून 2016 की धारा में साफ लिखा है कि आधार कार्ड से नागरिकता की बजाय सिर्फ निवास स्थान और पहचान प्रमाणित होता है। इसकी वजह यह है कि आधार कानून के तहत 182 दिनों तक भारत में लगातार रहने वाले व्यक्ति को सरकार चाहे तो आधार कार्ड जारी कर सकती है। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय भी इसे नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर चुका है। इसी तरह पैन कार्ड के लिए भी व्यवस्था दी गई है। पैन कार्ड का कानूनी आधार है कि व्यक्ति अर्जन कर रहा है और टैक्स दे रहा है।

आधुनिक विश्व व्यवस्था की एक खामी यह है कि यहां कानून की भाषा अलग होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कानूनी भाषा जटिल होती है और उसके शब्द जाल को आम आदमी नहीं समझ पाता। इसी आधार पर उसकी अवधारणाएं विकसित होती हैं और फिर वह किसी विषय का व्यवस्था को लेकर अपनी राय बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी को इन जटिलताओं की समझ है, शायद यही वजह है कि उनके कार्यकाल में देश के सैकड़ों गैरजरूरी कानूनों को या तो रद्द किया गया है या फिर कुछ नए संदर्भों वाले कानूनों में समाहित कर दिया गया है। आज के दौर में नागरिकता के दस्तावेज के रूप जब पासपोर्ट, आधार कार्ड , पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र को आखिरी और अंतिम प्रमाण मानने से इनकार किया जाता है तो अपनी लोक और आम धारणा के चलते आम आदमी इसके विरोध में उतर आता है। यही वजह है कि जब मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर के दौरान इन दस्तावेजों को आखिरी दस्तावेज मानने से इनकार किया गया तो इसका विरोध शुरू हुआ था। कुछ इसी अंदाज में पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी के बयान पर भी विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूछ लिया है कि पासपोर्ट बनाने से पहले पुलिस जब व्यक्ति का सत्यापन करती है तो आखिर वह किसका सत्यापन करती है और क्यों करती है? उनका यहां तक कहना है कि इससे लोगों के मन में यह भी संदेह उत्पन्न हो सकता है कि गैर भारतीयों को भी पासपोर्ट दिए जा रहे हैं?

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक भारत सरकार की ओर से नगारकिता के प्रमाण को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब पासपोर्ट मान्य नहीं, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर भरोसा नहीं और पैन कार्ड मान्य नहीं तो फिर आम नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे साबित करे। निश्चित तौर पर इसका भी सरकारी व्यवस्था में है। 20 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा था, 'जन्म की तारीख और जन्म-स्थान से जुड़े कोई भी दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि, ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।' इसमें रिलीज में कहा गया था कि जन्म की तारीख और जन्म स्थान से जुड़े कोई भी दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि, इन दस्तावेजों के बारे में आखिरी रूप से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसमें वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, इंश्योरेंस के कागजात, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या घर से जुड़े दस्तावेज या सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ऐसे ही अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट में और भी दस्तावेज शामिल किए जा सकते हैं ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को बेवजह परेशानी न हो।

बेशक कानून की भाषा अलग होती है और लोक का शब्द संसार अलग, लेकिन दोनों के बीच संतुलन होना ही चाहिए। लोक की समझ अपने तंत्र के लिए बेहतर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि लोक और कानून की भाषा के बीच के अंतर को पाट लिया जाए। अन्यथा गलतफहमियां होती रहेंगी और आखिरकार इससे नुकसान लोकतंत्र का होगा।

संपादकीय

सियासी नेतृत्व का पिछड़ापन

कांगड़ा के राजनीतिक नेतृत्व के पिछड़ेपन के लिए यहां के नेताओं का भोलापन, पहचान का संकट, आपसी मेलभाव तथा स्वीकार्यता की कमी मानी जा सकती है। कांग्रेस के नजरिए से कांगड़ा को सत्ता प्राप्ति का हक मिलता रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने तो बाकायदा कांगड़ा की शून्यता के दरवाजे खोलकर झांकने की कोशिश में सत्ता के कई संस्थान स्थापित किए। हालांकि सरकारों की सियासी बाध्यताओं ने कांगड़ा के उच्चारण तो बढ़ाए, लेकिन यहां कोई भी नेता महफूज न हुआ। अधिकतर सत्ता के दरबान बने या कांगड़ा की सियासी प्रतिभा के खिलाफ षड्यंत्रकारी बन गए। वीरभद्र हों, धूमल हों या जयराम ठाकुर, सभी ने अपना पंथ बनाने की कोशिश की, लिहाजा दरबारी होने का रुतबा मौजूदा सरकार के तहत स्थानीय निकाय चुनावों तक देखा गया। पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस के कब्जे ने भाजपा के नेतृत्व में कांगड़ा का शौर्य पस्त किया, तो धर्मशाला में भाजपा का अग्रणी चेहरा, कांग्रेस से भाजपा में आए सुधीर शर्मा की संगत में आगे बढ़ता देखा गया। यहां कांग्रेस की परीक्षा में कांगड़ा को सफल करने का कोई नायाब हीरा नहीं मिला, तो पड़ताल अगले चुनाव को सालती रहेगी। बेशक प्रतीकों में कांगड़ा का नाम हुआ। सबसे अधिक व सत्ता के नजदीक पहुंचाने में वीरभद्र की डॉक्ट्रिन श्रेष्ठ रही, लेकिन अपने-अपने सियासी अनुपात साधने की कोशिश में हर मुख्यमंत्री ने डमरू जरूर बजाए। वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री का शीतकालीन प्रवास, मंत्रिमंडलीय बैठकें, विधानसभा का शीतकालीन सत्र और धर्मशाला को शीतकालीन राजधानी का दर्जा दिया, तो प्रेम कुमार धूमल ने सचिवालय से खेल राजधानी के रुतबे से मुख्यालय को नवाजा। जयराम ने राज्य के चिंतन मनन में धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट, जी-ट्वंटी सम्मेलन के अलावा कई राष्ट्रीय पर्व और पहचान के इवेंट यहां आयोजित किए। वीरभद्र सिंह की रिवायतों से प्रभावित सुखविंद्र सुक्खू ने धर्मशाला तक कई विभागों, निगमों और बोर्डों के मुख्यालय पहुंचाए, तो संपूर्ण कांगड़ा घाटी को पर्यटन राजधानी घोषित कर-के, गगल एयरपोर्ट विस्तार को यकीनी बनाया।

चिंतन-मनन

शांति इंसान के अंदर है

पानी में मिला हुआ नमक दिखाई नहीं देता। इसका यह मतलब नहीं कि वह गायब हो गया। हालांकि आंख से नहीं देख सकते, पर जबान से उसे चख तो सकते हैं। मनुष्य के साथ ही कुछ ऐसा ही होता है। हम शांति को आंखों से नहीं देख सकते, परंतु हृदय से उसका अनुभव कर सकते हैं। वह शक्ति भी सब जगह है- थल में भी है, आकाश, वायु, जल और पेड़ों में भी है और उसी के होने की वजह से आप भी जीवित हैं। आप विश्वास करते हैं कि आपकी जन्मपुंडली में लिखा हुआ है, इसकी वजह से आप जीवित हैं, परंतु नहीं। कौन कब जाएगा, यह किसी को नहीं मालूम। कब क्या होगा, यह किसी को नहीं मालूम। पर लोग अपने जीवन के अंदर इसी चीज का विश्वास करके चलते हैं कि उनको मालूम है कि कल क्या होगा। आप जीते कहां हैं? आज में। कल तो आप जी नहीं सकते। अगर कल आएगा भी तो उसको आज का रूप लेना पड़ेगा। तो आप जीते कहां हैं? आज में। और आपकी आशाएं कहां हैं? कल में। आप चिंता किसकी करते हैं? कल की। और कल कभी आएगा नहीं। सारी जिंदगी आज में आपको जीना है। संस्कार यह डालने चाहिए कि आपके अंदर शांति है, उसे खोजो, उसको महसूस करो। अगर शांति-शांति कहने से ही शांति हो जाती तो अब तक तो हो जानी चाहिए थी। अब तक नहीं हुई है, तो कम से कम कुछ तो बदलिए। क्या बदलिए? मुंह को बंद कीजिए और अंतर्मुख होकर हृदय को खोलिए। क्योंकि शांति को पैदा करने की जरूरत नहीं है। शांति तो स्वयं आपके अंदर है, जैसे वह नमक जो पानी में मिला हुआ है, वैसे ही शांति भी आपके अंदर है। होश संभालने के साथ ही आप शांति, आनंद और चैन को ढूंढ रहे हैं। परंतु वह आपके हृदय के अंदर ही स्थित है। उसके अनुभव के लिए आपको इसे अपनाना पड़ेगा। इसे महसूस करने के लिए आप में इच्छा होनी चाहिए कि आप अपने जीवन में यह शांति चाहते हैं। जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक सारी बातें अधूरी हैं। जिस शांति की आपको तलाश है, वह शांति आपके अंदर है। कब तक रहेगी? जब तक आप जीवित हैं, तब तक रहेगी। आपकी सुंदरता कब बढ़ेगी? इस संसार के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, जिसे पहनकर आप दरअसल अच्छे लगेंगे? वह है शांति। आप शांति रूपी चादर ओढ़ेंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। वह मुस्कान सबसे सुंदर दिखाई देगी, तब आप असल में चमकेंगे। हृदय के दर्पण में आप अपनी परछाई देखेंगे, तो आप भी ऐसे आनंद से भर जाएंगे और कहेंगे-हे बनाने वाले, तुमने कितनी सुंदर चीज बनाई है जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं।

सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मोदी के नाम

सनत जैन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। इसके साथ ही पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए, जिन्हें अभी तक 34 देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा और इस सम्मान को लेकर विवादों का पिटारा भी भारत में खुलता हुआ नजर आ रहा है। सेशेल्स टैक्स हेवन देश है। इस देश की आबादी मात्र 1.1 लाख है। यह अफ्रीका का सबसे छोटा टापू है। इसका कुल क्षेत्रफल 459 वर्ग किलोमीटर है। इसकी गिनती समृद्ध देश के रूप में होती है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टैक्स हैवन देश के रूप में है। यह देश मत्स्य पालन, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं के लिए सारी दुनिया के देशों में पहचाना जाता है। यहां पर मुश्किल से 7 से 8000 भारतीय रहते हैं। इसमें से कुछ वर्षों में लगभग 2000 भारतीयों ने यहां की नागरिकता ली है। शेष भारतीय यहां पर जन्मजात रह रहे हैं। पनामा पेपर लीक में भी इस देश का नाम आया था। उस समय भी इसमें भारतीय नागरिकों के नाम थे। जिन्होंने अपना काला धन वहां जमा किया था। 2014 में जब केंद्र की सरकार बदली, उसके बाद यह माना जा रहा था, सरकार काला धन वापस लाने के लिए विशेष प्रयास करेगी। मोदी सरकार ने पनामा पेपर लीक मामले में जिन लोगों के नाम शामिल थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में कालाधन बड़ा चुनावी मुद्दा था। इस समय नरेन्द्र मोदी ने विदेशों में जमा कालाधन वापिस लाने का वायदा किया था। यह भी कहा था, हर परिवार को 15 लाख रूपया यों ही मिल जाएंगे। सेशेल्स जैसे देश से भारतीयों का जमा कालाधन वापस लाने का कोई प्रयास मोदी सरकार ने नहीं किया। उल्टे विगत वर्षों में जिस तरह से टैक्स हेवन देशों का पैसा भारत के शेयर बाजार एवं कारोबार में निवेश किया गया है, उसको लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। इस मामले में विनोद अडानी का नाम भी सामने आया था। सेबी और सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में बंद कर के रखा है।

इतने छोटे से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, लगभग तीन दिन तक रुकना, भारत में चर्चा का विषय बन गया है। भारत सरकार का कहना है, सेशेल्स हिंद महासागर का हिस्सा है। समुद्र का एक छोटा द्वीप होते हुए भी भारत के लिए सामरिक और समुद्री व्यापार के लिए उसका बड़ा महत्व है। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से सेशल्स को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रही है। पनामा पेपर लीक मामले तथा शेयर बाजार में निवेश को लेकर कई आरोप सामने आ चुके हैं। भारत सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। भारत में मोदी सरकार के लिए कई चुनौतियां सामने हैं। अयोध्या के राम मंदिर दान एवं चढ़ावे का मामला इस समय चरम पर है। कुछ ही दिनों बाद मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन शुरू हो गए हैं। विपक्ष बहुत आक्रामक है, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशेल्स जाना विवादों में आ गया है। उन्हें जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक और पहली बार नया सम्मान दिए जाने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। एक छोटे से टैक्स हेवन देश की यह यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए आगे चलकर कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न ना कर दे, इसको लेकर तरह-तरह की आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी काम करें, उन्हें किसी भी स्तर पर कोई नुकसान हो, यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों की संख्या कम नहीं है। इस तरह के विरोध होते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के विरोध पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। सेशेल्स यात्रा को लेकर जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, इसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरह के नुकसान के रूप में होगा, यह संभव ही नहीं है।

स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती है नकली दवाओं का कारोबार

मनोज कुमार अग्रवाल

आज कल देश के हर हिस्से में बड़र पैमाने पर नकली गैर मानक दवाओं के निर्माण और विपणन का धंधा चल रहा है आपको बता दें कि भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा निमार्ता होने के कारण इसे विश्व की फामेर्सी भी कहा जाता है। यहां विश्व की 60 प्रतिशत वैक्सीन और 20 प्रतिशत जैनेरिक दवाएं बनती हैं परंतु इनमें मिलावट का धंधा तेजी पकड़ रहा है। प्राण रक्षक दवाएं भी मिलावटी एवं नकली बनने लगी हैं।थोड़ा सा अधिक कमाई करने के चक्कर में बहुत से दवा निमार्ता देश मे गैर मानकीकृत स्तर

की दवा का निर्माण और निर्यात कर रहे हैं।

नकली दवाओं का अवैध कारोबार एक गंभीर वैश्विक संकट है जो मरीजों की जान जोखिम में डालता है और पूरी स्वास्थ्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ऐसी दवाएं जिनमें असली साल्ट या सक्रिय सामग्री नहीं होती या गलत मात्रा में होती हैं, वे नकली दवाओं के अंतर्गत आती हैं। एक अनुमान के मुताबिक, वैश्विक दवा बाजार का लगभग 10% हिस्सा नकली दवाओं से प्रभावित है। इसमें जीवन रक्षक दवाएं (कैंसर, लिवर रोग), एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और जीवनशैली से जुड़ी दवाएं शामिल हैं। ड्रग सिंडिकेट्स अवैध फैक्ट्रियों में खतरनाक रसायनों का उपयोग करके असली जैसी दिखने वाली पैकेजिंग तैयार करते हैं।ये दवाएं पारंपरिक थोक बाजारों के साथ-साथ अनधिकृत ऑनलाइन फार्मेसियों के माध्यम से भी बेची जा रही हैं। एंटीबायोटिक या गंभीर बीमारियों की दवाओं में मुख्य सामग्री न होने से मरीज ठीक नहीं हो पाता। कुछ मामलों में इनमें चूहे मारने का जहर, पेंट थिनर, चाक मिट्टी या भारी मात्रा में फेंटानिल मिला दिया जाता है। दूषित रसायनों के कारण किडनी, लिवर फेल होना या अचानक मौत होने का अत्यधिक खतरा रहता है।

आपको बता दें कि पिछले कुछ समय के दौरान घटिया व नकली दवाओं के सेवन से भारत तथा विश्व के चंद देशों में मौतों के कारण भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने घटिया और नकली दवाओं पर रोक लगाने और दवाओं की गुणवत्ता जांचने तथा उनके असली या नकली होने का पता लगाने के लिए दवाएं बनाने वाली इकाइयों की जांच शुरू कर रखी है।इसी श्रृंखला में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) ने मई, 2026 के लिए जारी मासिक गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट में बताया है कि देश भर में 159 दवा नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे।

सी.डी.एस.सी.ओ. के अनुसार केंद्रीय औषधि प्रयोग शालाओं ने 46 दवा नमूनों को नॉट आफ स्टैंडर्ड क्वालिटी (एन.एस. क्यू.) घोषित किया जबकि विभिन्न राज्यों

की औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 113 नमूनों को गुणवत्ता मानकों पर विफल पाया। मई, 2026 की रिपोर्ट में असम से किसी अनधिकृत निमार्ता द्वारा बनाई गई एक स्प्यूरियस (नकली) दवा का मामला भी सामने आया जिसने किसी दूसरी कम्पनी के ब्रांड नाम का दुरुपयोग किया।

इसी प्रकार केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला मुम्बई द्वारा हृदय रोगियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाला एडेनोसिन इंजैक्शन नकली पाए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश के औषधि प्रशासन ने यह इंजैक्शन बनाने वाली कम्पनी का लाइसैंस रद्द कर दिया है।

राजस्थान में 5 प्रसूताओं की मौत के मामले में नकली आक्सीटोसिन इंजैक्शन सप्लाई कारसेवाली कानी का लाइसेंस रहकर दिया गया है। इस संबंध में 23 जून को जारी आदेश के अनुसार अस्पतालों में सप्लाई किए गए टोसिन (आक्सीटोसिन) इंजैक्शन जांच में नकली पाए गए और प्रयोगशाला में परीक्षण में इन इंजैक्शनों में आक्सीटोसिन की मात्रा शून्य पाई गई।जांच में यह भी सामने आया कि उक्त फर्म ने अमृतसर स्थित एक लैबोरेटरी से (जिसका लाइसैंस अब रद्द किया जा चुका है) इसकी कुल 9300 डोज खरीदी थीं जबकि फर्म ने रिकार्ड में 10050 डोज बिकी दिखाई थी। ऐसे में यह जांच भी की जा रही है कि अतिरिक्त 750 इंजैक्शन कहां से आए !

राजस्थान में प्रसूताओं की मौत का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने इन मौतों के संबंध में मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए भारत सरकार से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने भारत सरकार को यह बताने को भी कहा है कि ये इंजैक्शन भारत के अलावा अन्य देशों में भी सप्लाई किए गए थे या नहीं और यदि ऐसा हुआ है तो किन देशों में सप्लाई हुए हैं ताकि समय रहते रोकथाम और निगरानी की कार्रवाई की जा सके।

इसी प्रकार की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में रोगियों की सुरक्षा तथा दवाओं की विश्वसनीयता यकीनी बनाने के लिए अब नकली और घटिया दवाओं के हानिकारक जाल को तोड़ने के लिए वैक्सीन, एंटी कैंसर और नार्कोटिक्स दवाओं पर क्यू.आर. कोड या बार कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है ताकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की मौत नकली दवाओं के कारण न हो।क्यू.आर. कोड में दवाई का अनूठा पहचान कोड, जैनेरिक और ब्रांड नाम, कम्पनी का नाम पता, बैच नंबर आदि सभी जरूरी जानकारियां दर्ज होंगी और बार कोड के खुलते ही दवाई के असली या नकली होने का पता चल जाएगा।

कैंसर जैसी बीमारी से रोगियों को बचाने के लिए क्यू. आर. कोड का नियम लागू करना सही है परंतु यह

आदेश केवल कुछ चुनिंदा रोगों की दवाओं के लिए नहीं बल्कि सभी दवाओं पर लागू करना चाहिए ताकि नकली दवाएं किसी की मौत का कारण न बनें। इसके साथ ही ऐसे कृत्यों में शामिल अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करके उन्हें उचित दंड दिया जाए।

केंद्र सरकार ने देश के शीर्ष दवा ब्रांडों की पैकेजिंग पर अनिवार्य क्यूआर कोड लागू किया है, जिसे स्कैन करके दवा की प्रामाणिकता जांची जा सकती है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और ड्रग्स विभाग की टीमें लगातार अवैध सिंडिकेट्स पर छापेमारी कर करोड़ों का नकली कच्चा माल जब्त कर रही हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत नकली दवाएं बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कठोर सजा और गैर-जमानती धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। उपभोक्ता को दवाएं हमेशा लाइसेंस प्राप्त और भरोसेमंद मेडिकल स्टोर या प्रमाणित फार्मेसियों से ही खरीदें। दवा के पत्तों पर स्पेलिंग की गलतियां, धुंधली छपाई, और सील टूटी होने जैसी विसंगतियों पर ध्यान दें। पैकेजिंग पर मौजूद क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करके बैच नंबर और निमार्ता की जानकारी को सत्यापित करें।हर खरीद पर कैश मेमो या पक्का बिल जरूर लें, जिस पर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट स्पष्ट लिखी हो। यदि दवा लेने पर कोई असर न हो या पैकेजिंग संदिग्ध लगे, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के पास शिकायत दर्ज कराएं।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

मूंगफली और बादाम से बनाएं स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन

सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में मूंगफली और बादाम जैसी चीजें सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। मूंगफली और बादाम से आप कई तरह के स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनके कुछ खास रेसिपीज, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

1. मूंगफली-बादाम हलवा

सामग्री
मूंगफली : 100 ग्राम
बादाम : 50 ग्राम
घी : 2 चम्मच
दूध : 1 कप
चीनी : स्वादानुसार
इलायची पाउडर : 1 चुटकी
विधि
मूंगफली और बादाम को हल्का भूनकर पीस लें। एक पैन में घी गर्म करें और इसमें मूंगफली-बादाम का पाउडर डालकर भूनें। इसमें दूध और चीनी डालें और धीमी आंच पर पकाएं। जब हलवा गाढ़ा हो जाए, तो इसमें इलायची पाउडर डालें।

गरमागरम हलवा तैयार है, इसे परोसें।

सामग्री
मूंगफली : 100 ग्राम
काजू : 50 ग्राम
आलू : 2 उबले हुए
हरी मिर्च : 1 बारीक कटी हुई
अदरक पेस्ट : 1 चम्मच
नमक : स्वादानुसार
तेल : टिक्का तलने के लिए
विधि मूंगफली और काजू को पीसकर पेस्ट बना लें। इसमें आलू, हरी मिर्च, अदरक पेस्ट और नमक मिलाकर टिक्की का मिश्रण तैयार करें। टिक्की का आकार देकर तेल में सुनहरा होने तक तलें। गरमागरम टिक्का हरी चटनी के साथ परोसें।

3. शकरकंद-मूंगफली चाट

सामग्री
शकरकंद : 2 उबले हुए
मूंगफली : 50 ग्राम भुनी हुई
हरा धनिया : 1 चम्मच
नींबू का रस : 1 चम्मच
नमक और चाट मसाला : स्वादानुसार
विधि
शकरकंद को छोटे टुकड़ों में काट लें। इसमें भुनी मूंगफली, हरा धनिया, नींबू का रस, नमक और चाट मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं। तैयार चाट को तुरंत परोसें।

4. पीनट बटर

सामग्री
मूंगफली : 1 कप
शहद : 1 चम्मच
तेल : 1 चम्मच (ऑप्शनल)
विधि
मूंगफली को हल्का भूनकर छिलका उतार लें। मूंगफली को मिक्सर में पीस लें। इसमें शहद और तेल डालें और फिर से ब्लेंड करें। क्रीमी टेक्सचर आने तक पीसते रहें। आपका घर का बना पीनट बटर तैयार है। इसे ब्रेड या रोटी के साथ खाएं। मूंगफली या पीनट बटर खरीदते समय मिलावट का ध्यान रखें। हमेशा ब्रांडेड और भरोसेमंद स्रोत से ही खरीदारी करें।

आम की गुठली से बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी मुखवास, स्वाद में होंगे बेहतरीन

आप आम की गुठली की सहायता से टेस्टी डिश बनाई जा सकती है। आज हम आपके साथ आम की गुठली के अंदर के बीज से चटपटे लच्छे बनाने की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं। यह काफी टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं।

गर्मियों में फलों का राजा आम हर किसी को खाना पसंद होता है। इसमें कई विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखते हैं। हालांकि लोग आम खाने के बाद लोग गुठली को फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम की गुठली भी कम फायदेमंद नहीं होती है। बल्कि आप आम की गुठली की सहायता से टेस्टी डिश बनाई जा सकती है। आज हम आपके साथ आम की गुठली के अंदर के बीज से चटपटे लच्छे बनाने की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं। यह काफी टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं। इसको मुखवास के नाम से भी जाना जाता है।

सामग्री
4 से 5 आम की गुठली
लाल मिर्च पाउडर
भुना जीरा पाउडर
चाट मसाला
काला और सफेद नमक
करें ये काम

सबसे पहले 4-5 आम की गुठली को अच्छे से धोकर बेकिंग ट्रे पर रखें। अब इसको 180 सेल्सियस पर करीब 10 से 15 मिनट के लिए माइक्रोवेव में पकाएं। बेक करने से यह कड़क हो जाएगा और आराम से कट जाएगा। फिर इस गुठली के अंदर से आपको बीज निकालें। अब कुकर में बीज और पानी डालकर 2 सीटी आने तक पकाएं। फिर बीज की स्किन निकालकर इसको लंबे-लंबे स्लाइस में काटें।

ऐसे बनाएं गुठली के लच्छे

सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म कर लें। अब इन बीज के स्लाइल्स को हल्का रोस्ट कर लें। अब इसके ऊपर से भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, नॉर्मल नमक डालें। इसको टॉस देने के बाद हल्का मिला दें। इस तरह से आम की गुठली से बना चटपटा लच्छा तैयार हो जाएगा।

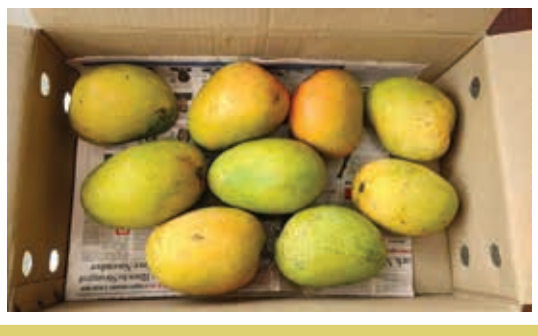

किचन में सिंक से आ रही है तेज बदबू, कॉफी का यह आसान नुस्खा आएगा काम

अमूमन हम सभी को यह समझ ही नहीं आता कि इस बदबू से निजात पाने के लिए क्या किया जाए, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी मॉर्निंग कॉफी की मदद से अपनी इस समस्या का हल कर सकती हैं।

किचन में सिंक एक ऐसी जगह होती है, जिसमें गंदे बर्तन व झूठा बचा हुआ होता है। जिसकी वजह से अक्सर किचन सिंक से गंदी बदबू आती है। जब सिंक से बदबू आने लगती है तो पूरी किचन में ही वह बदबू फैलते देर नहीं लगती है। भले ही आप अपनी किचन को कितना भी आर्गेनाइज्ड व साफ-सुथरा रखती हों, लेकिन अगर सिंक से बदबू आ रही है तो ऐसे में आपकी सारी मेहनत बर्बाद होते देर नहीं लगती।

अमूमन हम सभी को यह समझ ही नहीं आता कि इस बदबू से निजात पाने के लिए क्या किया जाए, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी मॉर्निंग कॉफी की मदद से अपनी इस समस्या का हल कर सकती हैं। कॉफी आसपास की गंध को सोखने और उसे फ्रेश बनाने में मददगार है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि आप कॉफी की मदद से किचन सिंक की गंदी बदबू को किस तरह दूर करें-

आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी-

इस्तेमाल की हुई कॉफी
उबला हुआ पानी
बेकिंग सोडा
नींबू रस या सिरका
कॉफी को किस तरह इस्तेमाल करें-

सबसे पहले सुबह कॉफी बनाने के बाद उसके ग्राउंड्स को फेंकने की जगह थोड़ा ठंडा होने दो। इसे पूरी तरह से सूखने मत दो।

अब इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा उस कॉफी में मिलाओ। इससे पाइप की भी हल्की सफाई हो जाएगी और बदबू भी अच्छे से हटेगी।

अब आप 2-3 चम्मच कॉफी का मिक्स सिंक के ड्रेन में डाल दो।

आप इसे ज्यादा ना डालें, नहीं तो पाइप जाम हो सकता है।

अब एक केतली पानी उबालें और फिर उस उबलते हुए पानी की डाल दो।

इससे कॉफी नीचे बहेगी और गंदगी भी साफ़ होगी। फ्रेशनेस की खुशबू तुरंत महसूस होगी।

अगर बदबू बहुत ज्यादा है तो कॉफी डालने के बाद थोड़ा नींबू रस या सिरका डाल दो, फिर गर्म पानी डालो।

कितनी बार इस्तेमाल करें

किचन सिंक की बदबू को दूर करने और उसे फ्रेश बनाए रखने के लिए हफ्ते में एक बार करना काफी है। ध्यान रखें कि रोज़ या बहुत ज्यादा कॉफी डालना पाइप ब्लॉक कर सकता है, इसलिए लिमिट में करो।

इस बात का रखें ध्यान

अगर तुम्हारे घर का पानी धीरे बहता है या पहले से ड्रेनेज धीमा है, तो ये ट्रिक ना आजमाएं। साथ ही, हर बार ढेर सारा गर्म पानी डालना जरूरी है ताकि कॉफी नीचे ठीक से जाए।

परफेक्ट तरीके से बेसन लड्डू बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

बेसन के लड्डू बाते समय घी डालने की टाइमिंग भी काफी मैटर करती है। कई बार लोग घी में पहले ही सारा घी डाल देते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में थोड़ा घी डालो ताकि बेसन अच्छे से भुने। इसके बाद आप बीच में ही थोड़ा-थोड़ा करके घी डालते रहो।

ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जिन्हें मीठा खाना काफी पसंद होता है। अक्सर वे ना केवल बाजार से मिठाई लाकर खाते हैं, बल्कि

घर पर भी मीठा बनाते हैं। अगर आप भी मीठे के दीवाने हैं और बेसन के लड्डू आपके फेवरिट हैं तो मुंह में घुल जाने वाली इस मिठाई को खुद घर पर ही बना सकते हैं। बेसन के लड्डू बनाना काफी आसान है, लेकिन इस सिंपल सी दिखने वाली रेसिपी में भी कई बार लड्डू बनाते वक्त कुछ छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं। कभी बेसन जल जाता है, तो कभी लड्डू अच्छी तरह से बंधते नहीं है।

हो सकता है कि आप भी घर पर बेसन के लड्डू बना रहे हों और आपके सामने यही दिक्कतें आ रही हों। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप घर पर बेसन के लड्डू बनाते समय फॉलो कर सकते हैं-

तेज आंच पर ना भूनें बेसन

अक्सर यह देखने में आता है कि जब लोग बेसन के लड्डू बनाते हैं तो बेसन को तेज आंच पर भूनने लग जाते हैं। हालांकि, ऐसा करने से बेसन भूनने की जगह जलने लगता है। इसलिए, आपको हमेशा धीमी आंच पर ही बेसन को भूनना चाहिए। जब हल्की सी खुशबू आए और बेसन का रंग सुनहरा होने लगे, तो समझे कि बेसन अच्छी तरह से भूनने लगा है।

सही समय पर डालें घी

बेसन के लड्डू बाते समय घी डालने की टाइमिंग भी काफी मैटर करती है। कई बार लोग घी में पहले ही सारा घी डाल देते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में थोड़ा घी डालो ताकि बेसन अच्छे से भुने। इसके बाद आप बीच में ही थोड़ा-थोड़ा करके घी डालते रहो।

बैटर को ठंडा ना होने दें

बेसन के लड्डू में शक्कर अच्छी तरह घुल जाए, इसके लिए जरूरी है कि आपका भुना हुआ बेसन हल्का गरम ही हो। अगर आपका बेसन एकदम ठंडा हो जाएगा तो इससे उसमें शक्कर अच्छी तरह मिक्स नहीं होता है। वहीं, अगर आप गरम बेसन में शक्कर मिक्स करते हैं तो इससे लड्डू भी बाइंड अच्छी तरह होंगे। साथ ही, इस बात का भी ख्याल रखें कि आप दानेदार चीनी की जगह बूरा या फिर पिसी हुई शक्कर डालकर मिक्स करें। दानेदार शक्कर का इस्तेमाल करने से लड्डू खाते समय वह मुंह में किरकिरा महसूस होगा।

स्वत्वाधिकार प्रकाशन एवं मुद्रक राजकुमार आमेटा के लिए स्मार्ट कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिन्टर्स, कोर्ट के सामने, माण्डलगढ़ से प्रकाशित एवं मुद्रित। मो. 9649222850 Email.smarthalchalnews@gmail.com